RNI No : JHAHIN/2021/83133
वर्ष- चार, अंक-03, जून- 2024 मूल्य: 20

राष्ट्रीय मासिक पत्रिका

नवजीवन संदेश

मजबूत विपक्ष के साथ

एनडीए की वापसी

झारखंड से दो मंत्रीः अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय तो संजय सेठ ने राज्यमंत्री की ली शपथ

पीएम मोदी-3.0 कैबिनेट में झारखंड के दो सांसदों को शामिल किया गया है. कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी ने केंद्रीय मंत्री की शपथ ली. वहीं, रांची से सांसद संजय सेठ ने राज्यमंत्री के रूप में शपथ ली.

झारखंड से दो मंत्री बनाए जाने के बाद रांची स्थित बीजेपी ऑफिस में जश्न शुरू हो गया. कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे फोड़े और एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाए.

बता दें कि कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी और रांची सांसद संजय सेठ दोनों दूसरी बार सांसद चुने गए हैं.

झारखंड की 14 में से आठ सीटों पर बीजेपी और एक सीट सहयोगी आजसू पार्टी को जीत मिली है. बीजेपी सांसद अन्नपूर्णा देवी पहले भी मोदी कैबिनेट का हिस्सा थीं. अन्नपूर्णा देवी को फेस बनाकर बीजेपी ओबीसी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर सकती हैं. वहीं, सांसद संजय सेठ के जरिए वैश्य समुदाय, जनजातीय समाज और अन्य को साधने की तैयारी है.

रांची लोकसभा सीट से दूसरी बार चुनकर आए सांसद संजय सेठ ने भी मंत्री पद की शपथ ली. बताया जा रहा है कि संजय सेठ का एक काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद आ गया था, जिसका इनाम उन्हें मंत्री पद के रूप में मिला है. जानते हैं कौन हैं संजय सेठः बताते हैं झारखंड में लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को लेकर जब चर्चा शुरू हुई तो राज्य इकाई की तरफ से संजय सेठ का नाम नहीं भेजा गया था. केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश इकाई की सिफारिश के खिलाफ जाकर संजय सेठ को रांची लोकसभा सीट से टिकट दिया था.. इस सीट से संजय सेठ ने जीत दर्ज कर भाजपा की झोली में डाल दी. अब उन्हें मोदी 3.0 कैबिनेट में जगह मिली है. संजय सेठ को मोदी कैबिनेट में जगह मिलने के बाद कहा जा रहा है कि संजय सेठ पीएम मोदी की निजी पसंद हैं. पिछले साल हुई भाजपा सांसदों की बैठक के दौरान मोदी ने उनकी खुले मन से तारीफ की थी. पीएम मोदी ने संजय सेठ की सांसद सांस्कृतिक महोत्सव पहल का उदाहरण देते हुए उनकी जमकर तारीफ की थी. संजय सेठ ने प्रधानमंत्री की सांसद खेल महोत्सव की तर्ज पर इसका आयोजन किया था. जिसका इनाम उन्हें अब मिल गया है. संजय सेठ पंजाबी वैश्य समुदाय से ताल्लुक रखते हैं. सेठ का परिवार रांची में स्पेयर पार्ट्स का व्यवसाय संभालता आया था. संजय सेठ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के करीबी माने जाते हैं. सेठ ने कानून की पढ़ाई की है. संजय 1980 के दशक में भाजपा के गठन के समय से ही जुड़े रहे हैं. उन्होंने ब्लॉक से लेकर प्रदेश स्तर तक के पदों पर काम किया है. 2019 के लोकसभा चुनाव में भी संजय सेठ ने रांची सीट से जीत दर्ज की थी. हाल में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें फिर से रांची से टिकट दिया. उन्होंने पार्टी के फैसले को सही साबित करते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्र मंत्री केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की बेटी यशश्विनी सहाय को 120512 वोटो से हरा दिया इसका इनाम उन्हें अब मिल रहा है.

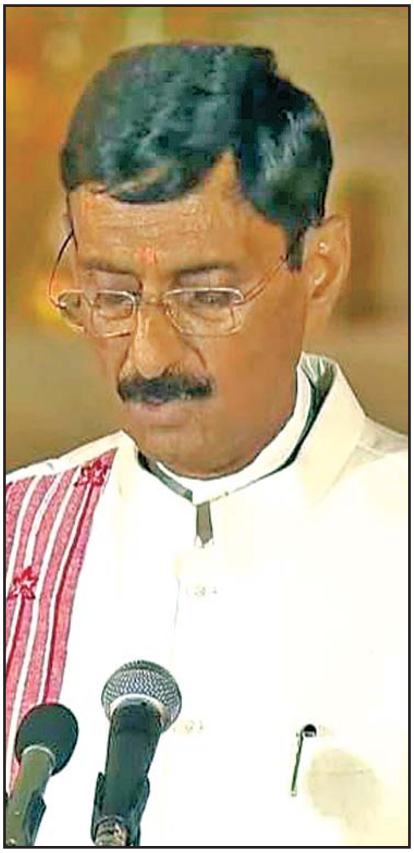

झारखंड से दो मंत्री बनाए जाने के बाद रांची स्थित बीजेपी ऑफिस में जश्न शुरू हो गया. कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे फोड़े और एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाए.

सांसद के रूप में अन्नपूर्णा देवी का यह दूसरा कार्यकाल होगा. लगातार दूसरी बार वो केंद्रीय मंत्री बनी है. 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वह आरजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थीं. राजद में रहने के दौरान उन्हें लालू प्रसाद यादव की करीबी नेताओं में से एक माना जाता था. बीजेपी में उन्हें संगठन और सरकार दोनों में बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई. 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्हें पहले झारखंड प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया था. बाद में बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हरियाणा का सह प्रभारी भी बनाया गया था. वह झारखंड और बिहार से चार बार विधायक भी रह चुकी हैं. उन्होंने झारखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया है. इसके अलावा वो सिंचाई, महिला एवं बाल कल्याण जैसे विभागों की मंत्री रही हैं.

पीएम मोदी के दोनों कार्यकाल में झारखंड को कैबिनेट में अहम जिम्मेदारी मिली थी. वर्ष 2014 में पहली बार पीएम मोदी कैबिनेट में सुदर्शन भगत को जनजातीय मामलों के राज्यमंत्री और जयंत सिन्हा को वित्त और नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री बनाया गया था. वहीं, दूसरी कार्यकाल में अर्जुन मुंडा और अन्नपूर्णा देवी को मौका मिला था.

RNI No: JHAHIN/2021/83133

नवजीवन संदेश

राष्ट्रीय मासिक पत्रिका

Web : navjeewansandesh.com

संबद्धता : प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (भाषा)

▪ वर्ष -4, ▪ अंक -03, ▪ कुल पृष्ठ -36

index

प्रधान संपादक

पंकज कुमार सिंह

संपादक

प्रभात मजुमदार

संपादक मंडल

जगन्नाथ मुंडा

सुनीता सिन्हा

श्रीमती छाया

रविप्रकाश

खेल डेस्क प्रभारी

चंचल भट्टाचार्य

मुख्यसंवाददाता

सत्येंद्र सिंह

छायाकार

नसीम अख्तर

संपर्क : 9431708799
9835437102

ईमेलः navjeewansandesh@gmail.com

इस बार के सबसे युवा सांसद... पेज-09

महाराष्ट्र में जोड़-तोड़ की राजनीति क्यों नहीं चली? पेज-13

हार के बाद अर्जुन मुंडा... पेज-24

टी-20 विश्व कप क्रिकेट में भारत सबसे ... पेज-31

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक और प्रकाशक पंकज कुमार सिंह द्वारा प्रथम तल, होटल आलोका कॉम्प्लेक्स रेडियम रोड, समीप कचहरी चौक, रांची-834001 (झारखंड) से प्रकाशित तथा मैसर्स डी.,बी. कॉर्प लि. प्लॉट नंबर 535 व 1272, लालगुटवा, पुलिस स्टेशन रातू रांची से मुद्रित.
संपादक : प्रभात मजुमदार* (*संपादक इस अंक में प्रकाशित समाचार के चयन एवं संपादन हेतु पीआरबी एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत उत्तरदायी)
आरएनआई नं.: JHAHIN/2021/83133

संपादकीय

लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना क्यों अहम ?

2024 का लोकसभा चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव रहा, जिसमें करीब 64 करोड़ लोगों ने वोट डाला. एक लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना क्यों अहम है?भारत का 2024 का लोकसभा चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव रहा, जिसमें करीब 64 करोड़ लोगों ने वोट डाला. भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और सियासी निगाह से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र . लेकिन लोकतंत्र होता क्या है? लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र, लोगों की मर्जी, उनकी पसंद, उनके प्रतिनिधि. 19 नवंबर, 1863 अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक भाषण में कहा था, “लोकतंत्र लोगों की सरकार है, जिसे लोग ही बनाते हैं और जो लोगों के लिए ही होती है.”

19वीं सदी में मशहूर इतिहासकार लॉर्ड एक्टन ने एक पादरी को खत में लिखा था, ‘पावर टेंड्स टू करप्ट, एब्सोल्यूट पावर टेंड्स टू करप्ट एब्सोल्यूटली’. हिंदी में इस अर्थ होगा कि सत्ता-मोह आपको भ्रष्ट बना देता है और सत्ता पूरी तरह आपके हाथ में होना आपको पूरी तरह भ्रष्ट बना देता है. यह कहावत आज भी उतनी ही पुख्ता है, जितनी 19वीं सदी में रही होगी.

लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है कि नेता जनता द्वारा चुने जाते हैं और उसके बाद होता है विपक्ष . किसी भी लोकतंत्र के बेहतर तरीके से काम करने के लिए जरूरी है कि उसमें असहमति और नाराजगी की गुंजाइश हो और सत्तारूढ़ सरकार पर निगाह हो.

मतदान की तारीखें करीब आते हुए भारत का विपक्ष काफी कमजोर लग रहा था. कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया में तमाम तरह की धांधलियों के आरोप लगा रही थी. देशभर से ऐसी रिपोर्ट आईं, जिनमें कहा गया कि लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं. ऐसी शिकायतें मुस्लिम-बहुल इलाकों से ज्यादा आईं.

कई वीडियो भी सामने आए, जिनमें कहा गया कि मुस्लिम-बहुल इलाकों में मतदान या तो बंद हो गया या उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया. देश में पहली बार ऐसा हुआ कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री जेल चले गए. वह भी देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री. चुनाव से कुछ महीनों पहले विपक्ष के प्रमुख नेता राहुल गांधी संसद से निलंबित कर दिए गए.

सत्ताधारी बीजेपी पर लगातार आरोप लगते रहे कि विपक्ष को दबाने के लिए जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल किया गया. यहां तक कि मुख्य विपक्ष पार्टी कांग्रेस और विपक्ष के कई नेताओं के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए थे. फिर जांच एजेंसियों से जुड़ा एक घोटाला भी सामने आया, जिसमें कहा गया कि जो लोग सरकार का साथ नहीं दे रहे थे, उन पर ईडी की कार्रवाई हुई. इस खुलासे पर देश के कई राजनीतिक पंडितों और विश्लेषकों की निगाहें टेढ़ी हुई थीं.

हालांकि, विपक्ष की कमजोरी के लिए पूरी तरह सत्तारूढ़ दल और सरकार को जिम्मेदार ठहराना गलत होगा. भ्रष्टाचार और परिवारवाद के लिए निशाने पर लिया जाने वाला विपक्ष अपनी बात बीजेपी के जितनी सफलता से जनता तक नहीं पहुंचा पाता. बीजेपी के मुकाबले कोई एक निर्विवादित मजबूत चेहरा न होना भी कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों के बुरे प्रदर्शन का जिम्मेदार माना जाता है.

यह समझना तो आसान है कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष कितना जरूरी है. लेकिन अगर विपक्ष मजबूत न हो, तो क्या होता है! वह भी बड़ा मसला है.

सबसे मोटी बात तो यह है कि कोई सरकार चाहे दक्षिणपंथी हो, समाजवादी हो या फिर साम्यवादी. गलतियां सभी करती हैं और करेंगी भी. पर उन गलतियों पर किसी की नजर होनी भी जरूरी है. मीडिया या न्यायालय यह काम अकेले नहीं कर सकते, इसलिए मजबूत विपक्ष आवश्यक होता है.

विपक्ष या विपक्षी पार्टियां जब मजबूत नहीं होती हैं, तो सत्ताधारी पार्टी को मनमानी करने की गुंजाइश मिलती है. इससे लोकतंत्र के बाकी तीनों धड़े- विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया कमजोर पड़ जाते हैं. ऐसे हालात में मीडिया फायदे के लिए या दबाव में एकतरफा हो जाता है और उसमें काम करने वाले लोगों को स्वतंत्रता और निष्पक्षता से काम करने में अड़चन आती है.

लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन. ऐसे में अगर सिर्फ बहुमत की आवाज ही जरूरी होती, तो विपक्ष नहीं होता. लोकतंत्र में सभी मतों और आवाजों को समान पायदान पर रखा जाता है. मजबूत विपक्ष से वे आवाजें भी बुलंद होती हैं, जो अपने उम्मीदवार को संसद तक नहीं पहुंचा पाए या सत्ता में हिस्सेदारी हासिल नहीं कर पाए.

सत्ता में एक ही पार्टी का होना या सिर्फ एक ही पार्टी का दबदबा होना इसलिए भी हानिकारक है, क्योंकि जब कोई चुनौती नहीं होगी और कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आएगी नहीं, तब तक जनता को पता ही नहीं चलेगा कि बेहतर प्रशासन की कितनी गुंजाइश है और क्या बदला जा सकता है, देश को कैसे बेहतर चलाया जा सकता है.

स्वतंत्रता संग्राम में भारत ने अंग्रेजों से निजात पाने के लिए भारी कीमत चुकाई थी. वह परिदृश्य ध्यान में रखते हुए भारत में मजबूत विपक्ष का होना जरूरी ही नहीं, बल्कि लाजिमी भी है. फिर देश के विपक्षी गठबंधन इंडिया ने एनडीए को मजबूत टक्कर दी है. एग्जिट पोल में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को भारी बढ़त दिखाई जा रही थी. इस लिहाज से विपक्ष ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है.

विपक्ष को बड़ी सफलता और उत्तर प्रदेश में मिली, जहां पिछले दो चुनावों से बीजेपी का बोलबाला है. बीजेपी राम मंदिर बनवाने का श्रेय भी लेती आई है, लेकिन फैजाबाद की ही सीट पर सपा ने बीजेपी को मात दी है.

अब तक के नतीजों और रुझानों से साफ है कि एनडीए गठबंधन सत्ता में वापसी कर सकती है, लेकिन लोकतंत्र के लिए खुशखबरी यह भी है कि विपक्ष के साथ अच्छी प्रतिद्वंद्विता और कई सीटों पर कड़ी मशक्कत के बाद ही सरकार बनेगी. किसी भी लोकतंत्र के लिए यह सुकून देने वाली खबर होगी.

मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री

24 राज्यों से 71 मंत्री बनाए 30 कैबिनेट और 36 राज्य मंत्री; 05 को स्वतंत्र प्रभार

नरेंद्र मोदी ने रविवार 9 जून की शाम लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वे जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा करने वाले दूसरे पीएम बन गए हैं। मोदी ने ईश्वर के नाम की शपथ ली। इसके बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली। मोदी समेत 72 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें 30 कैबिनेट मिनिस्टर और 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 36 राज्य मंत्री बनाए गए। राष्ट्रपति भवन में 7 देशों के लीडर्स के अलावा देश के फिल्म स्टार भी इस समारोह में पहुंचे। इनमें अक्षय कुमार, शाहरुख खान, विक्रांत मेसी और राजकुमार हिरानी शामिल हुए। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी मौजूद रहे।

नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार ने शपथ ले ली है. मोदी मंत्रिमंडल में कुल 72 लोगों को शामिल किया गया है. इसमें 30 कैबिनेट मंत्री, पांच राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं. मोदी पहली बार एक ऐसी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें अकेले बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है.ऐसे में मंत्रिमंडल गठन में बीजेपी सहयोगी पार्टियों का विशेष ख्याल रखा है. एनडीए के घटकों को खुश करने के अलावा बीजेपी क्षेत्रीय संतुलन साधने के साथ-साथ समाज के हर वर्ग को जगह देने की कोशिश की है. राष्ट्रपति भवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम सवा सात बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ ली.

जिन लोगों ने शपथ ग्रहण के लिए टेलीफोन आने की पुष्टि की है, उनमें टीडीपी के राम मोहन नायडू, जेडीयू के ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर,जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी, एलजेपी के चिराग पासवान,हम के जीतन राम मांझी,आरएलडी के जयंत चौधरी,अपना दल की अनुप्रिया पटेल के नाम शामिल हैं. इन लोगों को मंत्री भी बनाया गया है. दरअसल बीजेपी ने इन नामों के जरिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में संतुलन बनाने की कोशिश की है. वहीं राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव, डॉक्टर एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण जैसे पुराने लोगों को नए मंत्रिमंडल में जगह मिली है.यह भी तय है कि कैबिनेट समिति में शामिल चारों मंत्रालय गृह, रक्षा, वित्त और विदेश बीजेपी अपने ही पास रखेगी. ये मंत्रालय इन लोगों में से ही संभालेंगे.

नरेंद्र मोदी पहली बार गठबंधन की ऐसी सरकार का नेतृत्व करने जा रहे हैं, जिसमें उनकी पार्टी का बहुमत नहीं है. इस बार एनडीए में बीजेपी के 240 सदस्यों के अलावा टीडीपी के 16 और जेडीयू के 12 सदस्य शामिल हैं. ऐसे में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपने सहयोगी दलों को खुश रखने की भी चुनौती है. इससे इन दोनों दलों को अच्छी संख्या में मंत्रालय मिलने की संभावना है. मोदी की पिछली सरकार में जेडीयू शामिल नहीं हुआ था. वो जीतने मंत्रालय मांग रहा था, बीजेपी ने उतने देने से इनकार कर दिए थे.

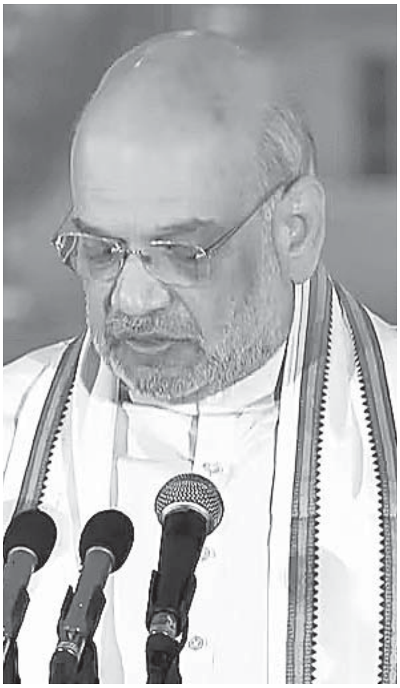

उस सरकार में बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत था, इसलिए ऐसा संभव हो पाया.लेकिन इस बार शायद ऐसा न होने पाए. वहीं बिहार से सबसे अधिक मंत्री भी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि वहां दो तरह की चुनौती है, एक तो जेडीयू और लोजपा (आर) के खुश रखना और दूसरा राज्य में अपना आधार बढाने के लिए अपने नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह देना, क्योंकि बिहार में बड़ी पार्टी होने के बाद भी बीजेपी जेडीयू की जूनियर पार्टी है.बीजेपी वहां अपने दम पर सरकार बनाने की कोशिश कर रही है. यही हाल आंध्र प्रदेश का है, जहां बीजेपी कभी सफल नहीं हो पाई.दक्षिण के इस राज्य में सफल होने के लिए बीजेपी दूसरे दलों पर निर्भर है. ऐसे में आंध्र प्रदेश में से भी अधिक सदस्य मंत्रिमंडल में दिख सकते हैं.

दक्षिण भारत के कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में बीजेपी की उल्लेखनीय मौजूदगी नहीं है. बीजेपी ने इस साल के चुनाव में केरल में एक सीट जीती है.वामपंथ और कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी की यह पहली जीत है. वहीं तमिलनाडु में बीजेपी ने अपना वोट शेयर बढ़ाया है. इसे देखते हुए बीजेपी ने नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में दक्षिण के राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है. बीजेपी बहुत समय से दक्षिण भारत में पैर पसारने की कोशिश कर रही है. लेकिन उसे अधिक सफलता नहीं मिली है, जैसा कि उसे उत्तर भारत के राज्यों में मिलती रहती है.

इसके अलावा बीजेपी ने मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय संतुलन और अपने छोटे-छोटे सहयोगियों को भी साधने की कोशिश की.इसी के तहत हर सहयोगी दल के सदस्यों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है. यह स्पष्ट बहुमत न होने का ही दबाव है कि बीजेपी ने इस बार चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को भी मंत्री बनाया है. इससे पहले 2019 के चुनाव में चिराग पासवान की लोजपा ने छह सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन उनके पिता जी के निधन के बाद उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी. बाद में पार्टी में टूट होने के बाद उनके चाचा पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्री बनाया गया था. इसी तरह से पहली बार सांसद बने माझी भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं. वह अपनी पार्टी के अकेले सदस्य हैं. केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने वाले वो मुसहर जाति के पहले व्यक्ति हैं.

इसी तरह से बीजेपी पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के अलावा पश्चिम बंगाल के नेताओं की भी मोदी मंत्रिमंडल में मौजूदगी दिख सकती है. बीजेपी पूर्वोत्तर के अपने वरिष्ठ नेताओं सर्बानंद सोनोवाल को मंत्री बनाया है. सोनो असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं. वहीं अरुणाचल प्रदेश से आने वाले किरेन रिजिजू को भी मंत्री बनाया गया है. वो पिछली सरकार में भी मंत्री थे. पूर्वोत्तर भारत में बीजेपी पिछले काफी समय से अच्छा प्रदर्शन कर रही है.वहीं बीजेपी बंगाल में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की लगातार कोशिशें कर रही है, इस वजह से वहां के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और शांतनु ठाकुर को मंत्री बनाया गया है. ठाकुर बंगाल के प्रभावशाली मतुआ समुदाय के नेता है. वो नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार में भी मंत्री थे.

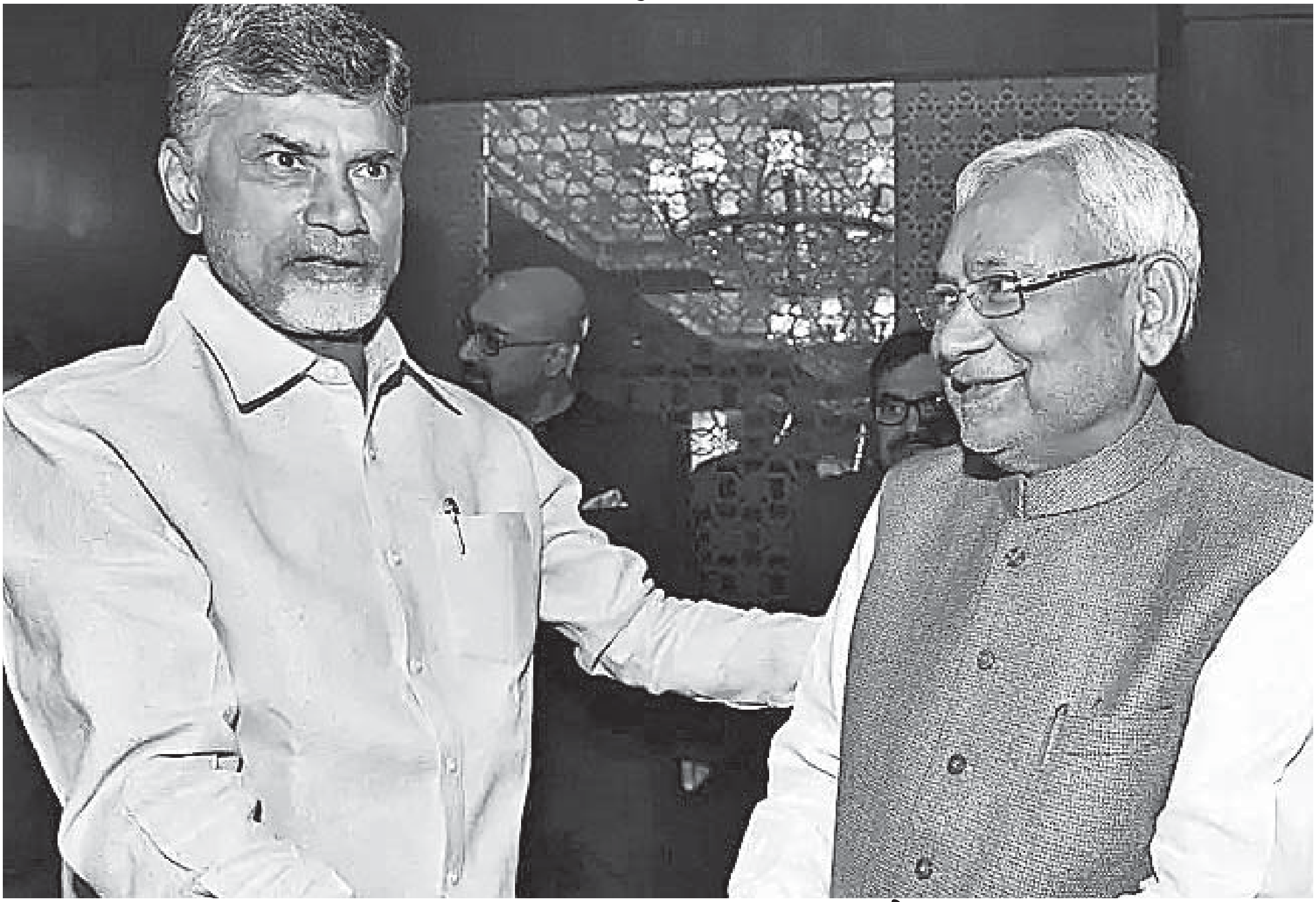

मोदी के लिए नीतीश और नायडू को साथ रखना बड़ी चुनौती क्यों?

नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल में कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे और किस तेवर के साथ काम करेंगे, यह अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भर करेगा.

पिछले दो बार से केंद्र में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिल रहा था लेकिन इस बार किसी तरह एनडीए को मिला है. ऐसे में मोदी को अपने कई एजेंडे किनारे रखने पड़ सकते हैं.

बीजेपी को 240 सीटों पर जीत मिली है और बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए. हालांकि एनडीए को 293 सीटें मिली हैं और यह सरकार बनाने के लिए पर्याप्त है.

चंद्रबाबू नायडू की तेलुगू देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने मिल कर 28 सीटें जीती हैं और एनडीए को बहुमत के आंकड़े तक ले गई हैं. वहीं इंडिया गठबंधन बहुमत से 40 सीटें पीछे रह गया है. नरेंद्र मोदी के लिए ये स्थिति बहुत सहज नहीं है, बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले दो कार्यकाल में काफी मजबूत स्थिति में थे.

नरेंद्र मोदी के पास गठबंधन सरकार चलाने का अनुभव भी नहीं है. गुजरात में जब वह मुख्यमंत्री थे, तब भी प्रचंड बहुमत वाली सरकार थी.

हक़ीक़त यह है कि बीजेपी की कमान मोदी के पास आने के बाद से एनडीए का कुनबा छोटा होता गया. अकाली दल और शिवसेना बीजेपी के दशकों पुराने सहयोगी रहे थे लेकिन दोनों कब का अलग हो चुके हैं. इस बार जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो उन्हें सरकार चलाने के लिए सबको साथ लेकर चलना होगा. उनके सामने सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी और चुनौती होगी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर चलना.

नरेंद्र मोदी के दिल्ली आने के बाद नीतीश कुमार और नायडू के संबंध बीजेपी से बहुत कड़वाहट भरे भी रहे हैं. नायडू और नीतीश 2014 में नरेंद्र मोदी के पहली बार प्रधानमंत्री बनने पर बीजेपी के विरोधी खेमे में रह चुके हैं और इस लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए में वापसी की है.

नायडू और नीतीश का रुख क्या होगा?

जब नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय से अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित किया तो वहाँ उन्होंने खासतौर पर एनडीए की इस जीत में चंद्रबाबू नायडू की आंध्र में बड़ी जीत और नीतीश कुमार की बिहार में जीत का ज़िक्र किया. आंध्र में तेलुगू देशम के पक्ष में फैसला आने के बाद एक्स पर चंद्रबाबू नायडू ने लिखा था, "आंध्र प्रदेश के लोगों ने हमें एक मजबूत जनादेश दिया है. यह जनादेश हमारे गठबंधन और राज्य के लिए लोगों के विश्वास का प्रतिबिंब है. अपने लोगों के साथ मिलकर, हम आंध्र प्रदेश का पुनर्निर्माण करेंगे और इसके गौरव को फिर से स्थापित करेंगे."

अपने ट्वीट में चंद्रबाबू नायडू ने तो एनडीए गठबंधन की बात कर दी लेकिन 12 सीटें जीतने वाले नीतीश कुमार ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

अंग्रेज़ी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कई बार नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश की लेकिन नीतीश

कुमार उनसे नहीं मिले. सम्राट चौधरी से ना मिलने और कोई प्रतिक्रिया ना देने को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. ख़ास कर तब जब सोमवार को कांग्रेस दफ्तर में कई नेताओं ने चेहरे पर मुस्कान के साथ ये कहा- "नीतीश जी सबके हैं." चर्चा ये भी है कि इंडिया ब्लॉक ने नीतीश कुमार को अप्रोच किया है. हालांकि जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने ये ज़रूर कहा कि " हम एनडीए के साथ थे और एनडीए के साथ ही आगे भी रहेंगे."

मोदी- नीतीश- चंद्रबाबू नायडू के रिश्ते : जब गुजरात में साल 2002 में दंगे हुए थे तो चंद्रबाबू नायडू एनडीए के पहले ऐसे नेता थे, जिन्होंने बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की थी. अप्रैल 2002 में टीडीपी ने मोदी के खिलाफ हिंसा को रोकने और सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों को राहत देने में में बुरी तरह फेल होने को लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया था. जब से आंध्र में टीडीपी की 16 सीटें आई हैं और अब जब नायडू किंगमेकर की भूमिका में दिख रहे हैं तो सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी का साल 2019 में आंध्र प्रदेश में दिया गया भाषण खूब शेयर किया जा रहा है. इस भाषण में नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को "अपने ससुर के पीठ में छुरा भोंकने वाला बताया था."

उन्होंने राज्य में एक चुनावी रैली में कहा था, "वो (चंद्रबाबू नायडू) खुद को मुझसे सीनियर मानते हैं, अच्छी बात है आप सीनियर हैं. लेकिन आप सीनियर हैं, पार्टी बदलने में, अपने ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में और आप सीनियर हैं एक के बाद एक चुनाव हारने में... उसमें तो मैं सीनियर नहीं हूं." अब जब चंद्रबाबू नायडू की बदलौत एनडीए दक्षिण के राज्य में बेहतर कर पाई है तो इस वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा.

मोदी और शाह का नायडू पर हमला: इसी दौरान अमित शाह ने भी एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को 'अवसरवादी' बताते हुए कहा था कि 'एनडीए के दरवाज़े उनके लिए हमेशा बंद हैं.' लेकिन टीडीपी की गठबंधन में वापसी साल 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हो गई. कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने नरेंद्र मोदी के इस क्लिप पर प्रतिक्रिया देते हुए नतीजे आने के बाद लिख- "सोच रहा हूं कि अब इस वीडियो का वो क्या करेंगे?" साल 2018 में चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर एनडीए का साथ छोड़ दिया था और केंद्र में अपने दो मंत्रियों को भी हटा दिया.

नायडू उस समय मोदी सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाए थे. ये अविश्वास प्रस्ताव तो पास नहीं हो पाया लेकिन अपने 16 सांसदों के साथ एनडीए से निकल गए थे. साल 2019 में गठबंधन से निकलने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने एक ट्वीट कर कहा था, "मोदी ने योजनाबद्ध तरीके से भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों को नष्ट कर दिया है. बीजेपी सरकार के शासन में संस्थागत स्वायत्तता और लोकतंत्र पर हमला हुआ है." सीबीआई से लेकर आरबीआई तक, यहाँ तक कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को भी नहीं बख्शा गया." लेकिन आज वो एनडीए के साथ हैं और मोदी के तीसरी बार सत्ता में काबिज होने में बड़े मददगार होंगे.

इसी तरह नीतीश कुमार ने जब साल 2013 में एनडीए छोड़ा तो उसकी वजह नरेंद्र मोदी ही थे.

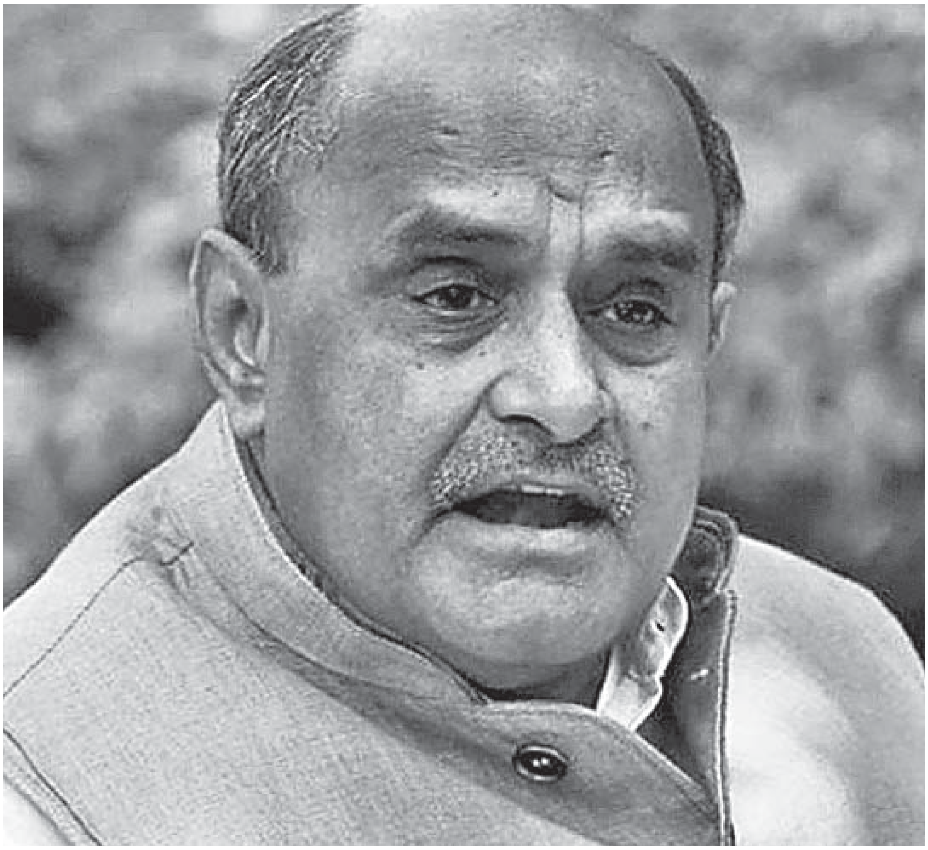

कांग्रेस दफ्तर में कई नेताओं ने चेहरे पर मुस्कान के साथ ये कहा- "नीतीश जी सबके हैं." चर्चा ये भी है कि इंडिया ब्लॉक ने नीतीश कुमार को अप्रोच किया है. हालांकि जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने ये ज़रूर कहा कि " हम एनडीए के साथ थे और एनडीए के साथ ही आगे भी रहेंगे."

तब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपने चुनावी अभियान का प्रमुख ही बनाया था. लेकिन नीतीश को अंदाज़ा हो गया था कि बीजेपी पीएम पद का उम्मीदवार उन्हें ही बनाएगी. नीतीश कुमार को यह बिल्कुल पसंद नहीं था.

नीतीश कुमार को लगता था कि वह मोदी के नेतृत्व में एनडीए में रहे तो उनके मुस्लिम वोटर अलग हो जाएंगे. यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने 2013 से पहले यानी 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को बिहार में चुनाव प्रचार तक करने नहीं आने दिया था. नीतीश ने ऐसा ही 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी किया था.

2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में अकेले ही मैदान में उतरी थी लेकिन दो सीटों पर सिमट गई थी. साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश ने आरजेडी के साथ चुनाव लड़ने का फ़ैसला किया और बंपर जीत मिली थी. दो साल बाद नीतीश फिर एनडीए में आ गए थे और 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से 39 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी.

2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बनी लेकिन एनडीए की सरकार में वो मुख्यमंत्री बने. फिर 2022 में नीतीश आरजेडी के साथ आ गए. लेकिन इस साल जनवरी में वो एक बार फिर पाला बदल बीजेपी के साथ आ गए. नीतीश कुमार का गठबंधन बदलना भारत की राजनीति में ऐसी प्रक्रिया बन गई है, जो हैरान नहीं करती लेकिन सस्पेंस बरकरार रहता है कि वो किसे कब किंग की भूमिका में ला दें. अब 12 सीटों के साथ नीतीश को अपने साथ बनाए रखना नरेंद्र मोदी के लिए चैलेंज होगा.

विपक्ष के पास एक उम्मीद है कि बीजेपी के ये दो दल साइड बदल सकते हैं और यही बीजेपी के लिए चिंता भी होगी. नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में कई ऐसे एजेंडे थे, जिन्हें गठबंधन वाली सरकार में पूरा करना आसान नहीं होगा. जैसे नीतीश और चंद्रबाबू नायडू वन नेशन वन इलेक्शन, समान नागरिक संहिता और पीएसयू में विनिवेश पर शायद ही तैयार हों. नरेंद्र मोदी आक्रामक आर्थिक नीतियां भी इन दोनों की सहमति के बिना लागू नहीं कर सकते हैं. एनआरसी और सीएए को लेकर भी विरोध बढ़ सकता है.

नरेंद्र मोदी के पास अटल बिहारी वाजपेयी वाला अनुभव नहीं है. वाजपेयी ने दर्जन भर से ज़्यादा पार्टियों को साथ लेकर एनडीए की सरकार चलाई थी और बीजेपी को हार्ड कोर एजेंडा किनारे रखना पड़ा था. ऐसे में नरेंद्र मोदी के पास दो विकल्प होंगे. पहला यह कि अपने एजेंडा किनारे रखें और दूसरा कि साझे एजेंडे पर आगे बढ़ें.

लोकसभा चुनाव 2024

इस बार के सबसे युवा सांसद

कांग्रेस के तीन युवा चेहरे पहुंचेंगे संसद

लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं. सबसे अधिक युवा आबादी वाले देश ने इस बार 30 साल से कम उम्र के सात सांसदों को चुना है. 18वीं लोकसभा के चुनावी नतीजों के आधार पर कह सकते हैं कि इस बार संसद में पिछली लोकसभा के मुकाबले युवा चेहरे अधिक नजर आएंगे. नई संसद में तीस साल से कम उम्र के सात सांसद होंगे. इसमें से चार सांसद तो महज 25 साल के हैं. खास बात यह है कि इन सात युवा सांसदों में से चार महिलाएं हैं, जो अलग-अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से आती हैं.

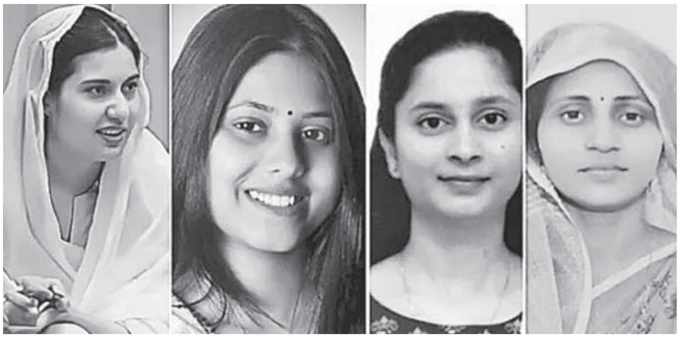

कांग्रेस की 26 वर्षीया नेता संजना जाटव ने राजस्थान की भरतपुर सीट से जीत दर्ज की है. उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी रामस्वरूप कोली को 51,983 वोटों से शिकस्त दी. संजना दलित समुदाय से हैं. जीत दर्ज करने के बाद वह राजस्थानी लोकगीत पर नाचते हुए जश्न मनाती नजर आईं. वह अब तक की सबसे युवा दलित महिला सांसदों में से एक हैं. कांग्रेस की ही प्रत्याशी प्रियंका सिंह जरकीहोली कर्नाटक की अनारक्षित सीट चिकोडी से जीती हैं. वह अब तक की सबसे युवा महिला आदिवासी सांसद हैं. उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार अन्नासाहब शंकर जोले को 90,834 वोटों से हराया. उनके पिता सतीश जरकीहोली भी कर्नाटक में कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे हैं. कर्नाटक की ही बीदर सीट ने संसद को एक और युवा चेहरा दिया है. 26 साल के सागर ईश्वर खांद्रे ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था. वह राज्य में कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले सबसे युवा उम्मीदवार रहे. उन्हें बीजेपी के अपने प्रतिद्वंद्वी भगवंत खुबा से 1,28,875 अधिक वोट मिले. केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री खुबा दो बार सांसद रह चुके हैं. ऐसे में सागर खंड्रे के विजेता बनने को बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है. हालांकि, सागर भी राजनीतिक परिवार से आते हैं. उनके पिता ईश्वर खांद्रे फिलहाल कांग्रेस सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री के पद पर हैं. उनके दादा भीमन्ना खांद्रे भी कांग्रेस का पुराना चेहरा रहे हैं.

समाजवादी पार्टी के 'जेनजी' सांसद

समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे तीन युवा चेहरे अब सांसद बनकर अपने-अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे. यूपी की कौशांबी सीट से पुष्पेंद्र सरोज ने जीत दर्ज की है. उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार विनोद कुमार सोनकर को 1,03,944 वोटों से हराया है. सोनकर इसी सीट से दो बार सांसद रह चुके हैं. सरोज 25 साल के हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं. मछलीशहर सीट से जीतने वाली प्रिया सरोज भी महज 25 साल की हैं. उन्होंने बीजेपी के मौजूदा सांसद भोलानाथ को 35,850 वोटों से हराया. प्रिया के पिता तूफानी सरोज तीन बार सांसद रह चुके हैं. यूपी की कैराना सीट से सपा की उम्मीदवार इकरा चौधरी ने 5,28,013 वोट हासिल किए. उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार और सांसद प्रदीप कुमार को 69,116 वोटों से हराया. 29 साल की इकरा के पिता चौधरी मुनव्वर हसन भी सपा से सांसद थे. 2008 में एक कार हादसे में उनका निधन हो गया था. इस चुनाव में एसपी ने यूपी में कुल 37 सीटें जीती हैं. यह किसी लोकसभा चुनाव में सपा का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है.

बिहार की सबसे युवा सांसद बनीं शांभवी

लोक जनशक्ति पार्टी की टिकट पर 25 वर्षीया शांभवी चौधरी ने समस्तीपुर सीट से जीत हासिल की. उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार सुन्नी हजारी को 1,87,251 से हराया. शांभवी के पिता अशोक चौधरी जेडीयू नेता हैं. वह कांग्रेस छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए थे.

कितनी युवा हुई भारतीय संसद

17वीं लोकसभा में केवल 12 फीसदी सांसद ही 40 साल से कम उम्र के थे. पिछली लोकसभा की औसत उम्र 54 साल थी. तब बीजू जनता दल से 25 वर्षीय चंद्राणी मुर्मू सबसे युवा सांसद बनी थीं. यहां तक कि 2019 में गठित मोदी कैबिनेट की औसत उम्र भी 60 साल थी. भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है. यहां देश की आधी से अधिक आबादी की उम्र 30 साल से कम है. 18वीं लोकसभा में युवा सांसदों की संख्या जरूर बढ़ी है, लेकिन देश में युवाओं की आबादी को देखते हुए इसे पर्याप्त नहीं माना जा सकता. भारत में लोकसभा चुनाव के लिए 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल की उम्र निर्धारित है. हालांकि, पिछले साल एक संसदीय समिति ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की तय उम्र 25 से घटाकर 18 साल करने की सिफारिश की थी. कानून और कार्मिक संबंधी समिति का मानना था कि ऐसा करने से युवाओं को लोकतंत्र का हिस्सा बनने का समान अवसर मिलेगा. समिति ने अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण देते हुए कहा था कि युवा जिम्मेदार और भरोसेमंद प्रतिभा साबित हो सकते हैं. यहां इस बात का जिक्र भी जरूरी है कि अधिकतर युवा चेहरे, जो इस बार नई संसद का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उनका ताल्लुक राजनीतिक परिवारों से है. हालांकि, भारतीय राजनीति के संदर्भ में परिवारवाद का मुद्दा नया नहीं है.

बीजेपी के पक्के सिपाही... मोदी सरकार 3.0 में फिर मंत्री बने जी किशन रेड्डी

तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी. किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद सीट से कांग्रेस उम्मीदवार को 49,944 वोटों से हराया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की नई सरकार में जी. किशन रेड्डी को केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री बनाया गया है। मोदी के दूसरे कार्यकाल में प्रह्लाद जोशी के पास यह मंत्रालय था। सतीश चंद्र दुबे को कोयला एवं खनन मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद दिया गया है। जानते हैं दोनों मंत्रियों के बारे में

जी. किशन रेड्डी

तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी. किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद सीट से कांग्रेस उम्मीदवार को 49,944 वोटों से हराया है। इससे मोदी सरकार 2.0 में केंद्रीय मंत्री रह चुके जी. किशन रेड्डी का पूरा नाम गंगापुरम किशन रेड्डी है। उन्हें किशनअन्ना के नाम से भी जाना जाता है। गंगापुरम किशन रेड्डी पिछली सरकार में पर्यटन, संस्कृति और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत रहे। रेड्डी 2019 से सिकंदराबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने 2009 में आंध्र प्रदेश विधानसभा में भाजपा के नेता के रूप में कार्य किया और तत्कालीन आंध्र प्रदेश के राज्य भाजपा अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के बाद इसे छोड़ दिया।

1977 में जनता पार्टी से पॉलिटिकल करियर की शुरुआत

जी किशन रेड्डी का जन्म 15 जून 1960 को तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के तिम्मापुर गांव में हुआ था। उनके माता-पिती, जी स्वामी रेड्डी और अंडालम्मा थे। उन्होंने टूल डिजाइन में डिप्लोमा किया है। रेड्डी ने अपने करियर की शुरुआत 1977 में जनता पार्टी के एक युवा नेता के रूप में की थी। 1980 में भाजपा के निर्माण के बाद वे इसमें शामिल हो गए। उन्हें 2002 से 2005 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।

लगातार तीन बार विधायक चुने गए, फिर बने सांसद

रेड्डी 2004 में हिमायतनगर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक के रूप में चुने गए थे, इसके बाद, 2009 और 2014 में वे अंबरपेट विधानसभा क्षेत्र से चुने गए। 30 मई 2019 को, उन्होंने भारत सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पद की शपथ ली और 2021 में उनका प्रमोशन कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में हुआ। इसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश विधानसभा में बीजेपी की ओर से फ्लोर लीडर की जिम्मेदारी संभाली है। पिछले साल उन्हें प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी गई।

सतीश चंद्र दुबे

सतीश चंद्र दुबे भारत की राजनीति में जाना पहचाना चेहरा हैं। वे 16वीं लोकसभा में सांसद रह चुके हैं और लगातार दो बार विधायक भी चुने जा चुके हैं। सतीश चंद्र इस समय बीजेपी के बिहार से राज्यसभा सांसद हैं। बतौर सांसद यह उनका दूसरा कार्यकाल है जो की साल 2028 तक चलने वाला है। मोदी कैबिनेट 3.0 के सदस्य के रूप में उन्होंने रविवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई।

30 वर्ष की उम्र में चनपटिया विधानसभा से बने विधायक

महज 30 वर्ष की उम्र में चनपटिया विधानसभा से भाजपा विधायक के तौर पर निर्वाचित हुए सतीश चंद्र दुबे 49 वर्ष की उम्र में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने वाल्मीकि नगर से बीजेपी को जीत दिलाई थी। उस समय उन्होंने कांग्रेस के पूर्णमासी राम को हराया था। इससे पहले साल 2010 में नरकटियागंज से बिहार विधानसभा के लिए चुने जा चुके हैं। वे श्रम संबंधी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करते थे। साल 2014 से लेकर अब तक वो श्रम मंत्रालय, परामर्शदात्री समिति, ऊर्जा मंत्रालय और नवीन और पुनर्नवीनीकरण मंत्रालय के सदस्य रहे हैं।

वर्ष 1975 में नरकटियागंज प्रखंड के हरसरी गांव निवासी स्व इंद्रजीत दुबे व स्व पशुपति देवी के घर में जन्मे सतीशचंद्र दुबे ने मैट्रिक की पढ़ाई हाई स्कूल, नरकटियागंज तथा इंटरमीडिएट की पढ़ाई टी पी वर्मा कॉलेज से की है। श्री दुबे की धर्मपत्नी डा अल्का कुमारी ने उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुए पीएचडी की डिग्री हासिल की है।

कृषि और डेयरी से जुड़े है सतीश चंद्र

पेशे से कृषि कार्य करने वाले सतीश चंद्र के कृषि और डेयरी से जुड़े फार्म भी हैं। राज्यसभा सांसद को दो पुत्रियां व एक पुत्र है। बड़ी पुत्री विजयालक्ष्मी 8 वर्ष की है जबकि एक पुत्री श्रीलक्ष्मी व पुत्र शिवांश डेढ़ वर्ष के हैं। राज्यसभा सांसद तीन भाई और एक बहन हैं। बहन मीना देवी की शादी बगहा के मेहूडा में हुई है। सांसद के अग्रज अशोक कुमार दुबे व प्रदीप कुमार दुबे हैं।

बीसीसीएल का सामयिक भव्य आयोजन

दिल्ली में स्टील सेक्टर के उपभोक्ताओं के साथ सम्मेलन एवं परिचर्चा-सत्र का आयोजन किया

कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) ने 11 जून को होटल ली मेरिडियन, नई दिल्ली में स्टील सेक्टर के अपने मूल्यवान उपभोक्ताओं के साथ एक सम्मेलन एवं संवादात्मक परिचर्चा-सत्र का सफलतापूर्वक आयोजन किया. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्टील उद्योग के समक्ष चुनौतियों का समाधान करने के लिए कारोबारी प्रक्रियाओं को आसान बनाना तथा उद्योग से संबंधित नवीनतम विकास के बारे में जानकारी देना और चर्चा करना था. स्टील सेक्टर के उपभोक्ताओं के लिए कोकिंग कोयले के लिंकेज को उदार बनाया गया है, जिसके तहत इस्पात संयंत्रों को मौजूदा और/अथवा बनने वाली नई कोकिंग कोल वाशरियों एवं किसी भी अन्य वाशरी उत्पाद उपभोग करने वाले प्लांटों जैसे सीपीपी, सीमेंट, टेक्सटाइल, पेपर आदि के साथ समय-सीमा में लचीलेपन के साथ-साथ कंसोर्टियम बनाने की अनुमति दी गई है. इसका उद्देश्य कोकिंग कोल आयात प्रतिस्थापन और "आत्मनिर्भर भारत" को बढ़ावा देना भी है.

इस कार्यक्रम में देश में सबसे अधिक कोकिंग कोयला उत्पादक के रूप में बीसीसीएल की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया. उल्लेखनीय है कि बीसीसीएल देश के कुल कोकिंग कोयला उत्पादन में 50% से अधिक योगदान के साथ भारत मे सर्वाधिक कोकिंग कोयला का उत्पादन करता है. इस दौरान देश के विकास और इस्पात क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को समर्थन देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, बीसीसीएल ने कोयले की गुणवत्ता और संधारणीय प्रथाओं के प्रति भी अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया.

कार्यक्रम में आगामी ट्रांच-VII स्टील (कोकिंग) लिंकेज के ऑक्शन में कंपनियों के एसोसिएशन को लिंकेज ऑक्शन में बोली लगाने की अनुमति, कोकिंग कोल वाशरी

की स्थापना के लिए समय सीमा में लचीलेपन के साथ ही कंपनियों के संघ को अवसर प्रदान करने, कोकिंग कोल आयात प्रतिस्थापन और कोयला गुणवत्ता जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गयी.

कार्यक्रम में कोयला मंत्रालय के अपर सचिव श्री एम. नागराजू, कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक (विपणन) श्री मुकेश चौधरी और बीसीसीएल के सीएमडी श्री समीरन दत्ता के साथ-साथ बीसीसीएल से निदेशक (वित्त) श्री राकेश कुमार सहाय, डीटी (ओपी) श्री एस. के. सिंह, डीटी (पीएंडपी) श्री एस. नागाचारी और जीएम (विपणन और बिक्री) श्री हितेश वर्मा की उपस्थिति रही.

इस कार्यक्रम में देश भर की सभी प्रमुख इस्पात कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया, जिनमें सेल, आरआईएनएल, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील, जेएसडब्ल्यू-भूषण पावर एंड स्टील, रश्मि मेटालिक्स, एनएमडीसी स्टील, सनफ्लैग स्टील, जय बालाजी इंडस्ट्रीज आदि जैसी प्रमुख फर्मों के प्रमुख हितधारक शामिल थे. भारतीय इस्पात संघ, अखिल भारतीय इंडक्शन फर्नेस एसोसिएशन, भारतीय खनिज उद्योग महासंघ, कोयला उपभोक्ता संघ आदि ने कई उद्यमियों के साथ भाग लिया, जो देश में आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने के लिए कोकिंग कोल वाशरी स्थापित करने के इच्छुक हैं. विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों ने सीआईएल/बीसीसीएल की पहलों में व्यापक रुचि दिखाते हुए अपने विचार साझा किए. कोयला मंत्रालय के अपर सचिव श्री एम. नागराजू ने बीसीसीएल के रणनीतिक महत्व और देश में कोकिंग कोयले आवश्यकता और बीसीसीएल की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया.

बीसीसीएल के अध्यक्ष- सह- प्रबंध निदेशक श्री समीरन दत्ता ने कहा, "यह संवादात्मक सत्र इस्पात क्षेत्र में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है. हमारे प्रयास 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, और हम अपने उपभोक्ताओं को उच्चतम गुणवत्ता वाले कोकिंग कोल के साथ समर्थन देने के लिए समर्पित हैं."

कार्यक्रम का समापन प्रश्नोत्तर सत्र के साथ हुआ, जिसमें प्रतिभागियों को सीधे सीआईएल और बीसीसीएल टीम के विपणन और विक्रय विभाग से जुड़ने और भविष्य के सहयोग पर अंतर्दृष्टि साझा करने का अवसर मिला. यह विशेष कार्यक्रम अत्यधिक सफल रहा, और सभी प्रतिभागियों ने भविष्य में इसके सकारात्मक परिणामों की आशा व्यक्त की.

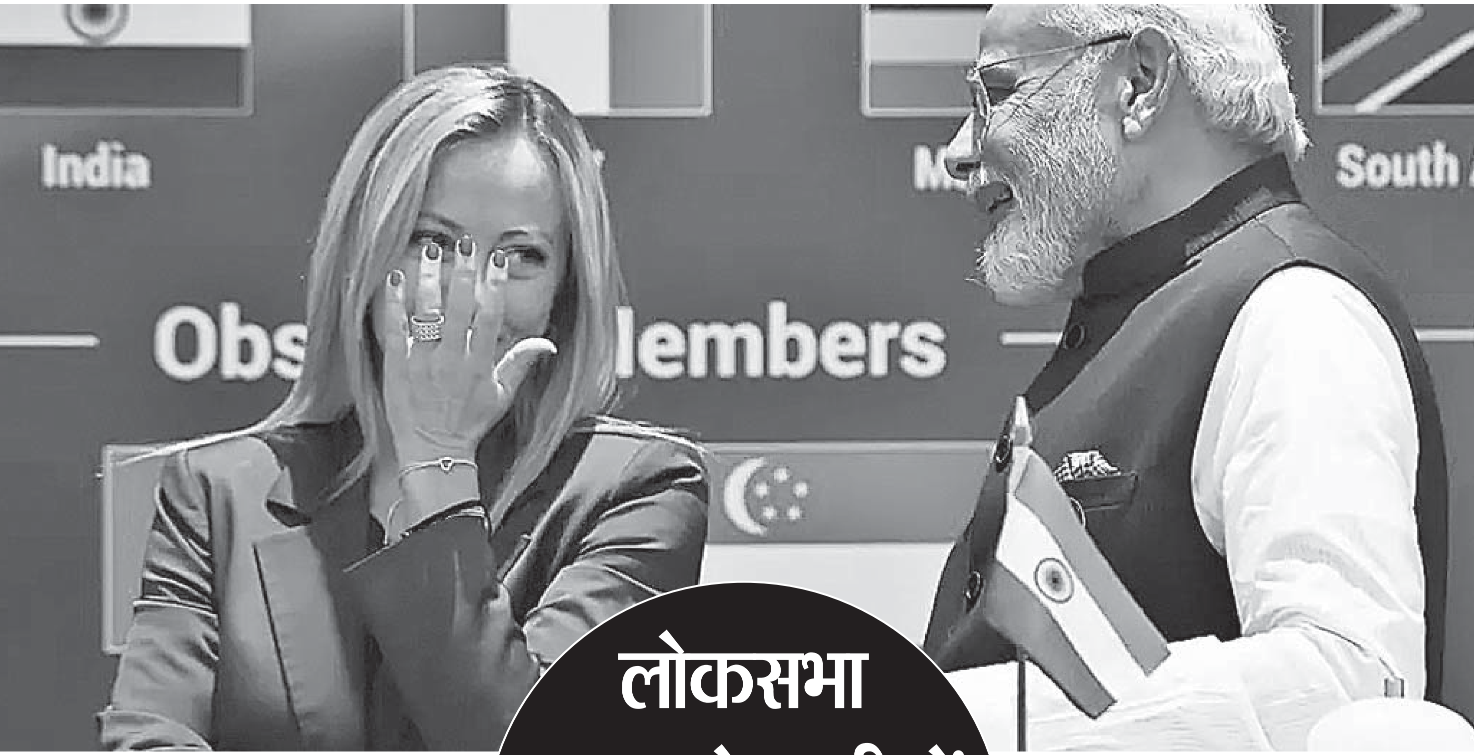

लोकसभा चुनाव के नतीजों पर दुनिया ने क्या कहा

नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी के लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीतने पर पूरी दुनिया से प्रतिक्रियाएं आई हैं. अमेरिका ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जीत बताया.

अमेरिका ने दुनिया के सबसे विशाल चुनाव पूरे हो जाने पर भारत को बधाई दी है. व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के प्रवक्ता जॉन कर्बी ने कहा कि भारत के लोगों ने अपनी इच्छाएं जाहिर कर दी हैं. पश्चिमी देशों से लेकर भारत के पड़ोसियों तक कई नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने जाने पर बधाई दी. बधाई देने वालों में नेपाल, मॉरीशस और भूटान से लेकर मालदीव के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज़ू तक शामिल हैं जिनके सत्ता में आने के बाद से भारत और मालदीव के रिश्तों में कुछ तनाव रहा है.

सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए आम चुनाव जीतने पर बधाई. मैं दोनों देशों की साझा स्थिरता और उन्नति के लिए मिलकर काम करने को लेकर उत्साहित हूं.”

श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ ने भी बधाई संदेश भेजा.

जापान सरकार के प्रवक्ता योशीमासा हायाशी ने भारत जैसे ‘महत्वपूर्ण साझीदार’ का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे नरेंद्र मोदी को बधाई दी. उन्होंने कहा, “हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले सत्ताधारी गठबंधन की जीत पर उन्हें बधाई देते हैं.”

पश्चिम से बधाई : इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने नरेंद्र मोदी को ट्वीट कर बधाई दी और भारत व इटली के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करने की इच्छा जताई. उन्होंने लिखा, “चुनावों में जीत पर नरेंद्र मोदी को बधाई. भविष्य के लिए उन्हें मेरी शुभकामनाएं. मुझे पूरा यकीन है कि हम भारत और इटली के बीच दोस्ती को मजबूत बनाने के लिए सहयोग जारी रखेंगे.”

अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने भारत और उसके मतदाताओं की विशाल चुनावी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए तारीफ की. उन्होंने कहा, “हम भारतीयों के इतनी विशाल चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने और उसे पूरी करने के लिए भारत सरकार और उसके मतदाताओं की तारीफ करते हैं.”

मिलर ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि भारत और अमेरिका के बीच करीबी सहयोग जारी रहेगा. यह एक महत्वपूर्ण साझीदारी है, सरकार के स्तर पर भी और लोगों के स्तर पर भी. और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह जारी रहेगी.”

इसके अलावा लोकसभा चुनाव में जीत पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नरेंद्र मोदी को बधाई पत्र भेजा है. संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेश ने भी भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सफलता पर बधाई दी है. उन्होंने कहा, “भारत के लोगों को लोकतंत्र के इस विशाल अभ्यास पर बधाई.”

क्या बोले नरेंद्र मोदी?

तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह ‘विकसित भारत बनाने के लिए’ सभी राज्यों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, चाहे वहां किसी की भी सरकार हो. चुनाव के नतीजे आने के बाद मंगलवार शाम को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बननी तय है. इसके लिए मैं देशवासियों का ऋणी हूं. यह विकसित भारत की जीत है.”

उन्होंने कहा कि 1962 के बाद यह पहली बार है कि कोई सरकार अपने दो कार्यकाल पूरे करने के बाद लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटी है.

विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को लेकर मोदी ने कहा, “पूरा गठबंधन, सारे विरोधी मिलकर उतनी सीटें नहीं जीत पाए, जितनी बीजेपी ने जीती. NDA के तीसरे कार्यकाल में देश कई बड़े फैसलों का नया अध्याय लिखेगा.”

नरेंद्र मोदी ने कहा, “आज की यह विजय, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है. यह भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है. यह विकसित भारत के प्रण की जीत है. यह सबका साथ-सबका विकास, इस मंत्र की जीत है. ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है.”

महाराष्ट्र में जोड़-तोड़ की राजनीति क्यों नहीं चली?

कहा जाता है कि देश में राजनीतिक बदलाव की बयार महाराष्ट्र से शुरू होती है.लोकसभा चुनाव के नतीजों से भी यही तस्वीर नज़र आ रही है. महाविकास अघाड़ी (उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी) ने महायुति (बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिव सेना और अजित पवार की एनसीपी) को पछाड़कर शानदार सफलता हासिल की है. इन नतीजों का राज्य की राजनीति पर दूरगामी असर पड़ेगा. आइए समझते हैं, उन कारणों को जो महाराष्ट्र की राजनीति को एक नई दिशा देते हैं. लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ गए हैं. सत्तारूढ़ बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और इस वजह से राज्य के साथ-साथ देश की राजनीति की तस्वीर बदल गई है या बदलने लगी है. यह राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए और इंडिया गठबंधन और महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच सीधी लड़ाई थी. बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 293 सीटें और इंडिया गठबंधन को 233 सीटों पर जीत मिली है. महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें महायुति और 30 सीटें महाविकास अघाड़ी ने जीती हैं. महाराष्ट्र में बहुत कड़ा मुक़ाबला हुआ है. दरअसल, हाल के दिनों में महाराष्ट्र में ऐसी कांटे की टक्कर कम ही देखने को मिली थी. महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच सीधी लड़ाई हुई. वंचित अघाड़ी भी मैदान में थी लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी. महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और मुंबई में महाविकास अघाड़ी का काफ़ी विस्तार हो चुका है. मुंबई में भी शिवसेना (उद्धव ठाकरे समूह) ने सबसे अधिक सीटें जीतीं, इसलिए इसका प्रभाव आगामी विधानसभा चुनाव और नगर निगम चुनावों में दिखाई देगा. इस चुनाव में कांग्रेस ने विदर्भ का गढ़ फिर से हासिल कर लिया है जबकि शरद पवार की एनसीपी पश्चिमी महाराष्ट्र में अपना गढ़ बचाने में कामयाब रही है. ज़ाहिर है 2019 के लोकसभा चुनाव में 41 सीटें जीतने वाले महायुति को सिर्फ 17 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा. महाविकास अघाड़ी ने ज़ोरदार प्रदर्शन करते हुए 30 सीटों पर जीत हासिल की है. इस साल के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जो प्रमुख बातें देखने को मिलीं, उनमें से एक है महायुति के तीन केंद्रीय मंत्रियों समेत कई दिग्गज उम्मीदवारों की हार. राज्य में जहां बीजेपी की ताकत घटी है, वहीं कांग्रेस की ताकत बढ़ी है. हिंदुत्व पर केंद्रित रही महाराष्ट्र की राजनीति में अब गठबंधन राजनीति का प्रभाव बढ़ने जा रहा है.

लोकसभा चुनाव से पहले महायुति एकजुट दिख रही थी जबकि महाविकास अघाड़ी एकजुट रहने के लिए संघर्ष कर रही थी. दरअसल, महाविकास अघाड़ी ने एकजुट होकर इस चुनाव का सामना किया जबकि चुनाव से पहले महायुति में काफी असमंजस की स्थिति थी. 2014 और 2019 की तुलना में इस साल लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है. पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए अपना प्रदर्शन दोहरा नहीं पाई है. ऐसा तब है जब बीजेपी ने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को अपने पाले में किया था. जैसे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और मिलिंद देवरा को चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल किया गया था. लेकिन बीजेपी की ये सारी रणनीति काम नहीं आई.

आइए जानते हैं, महाराष्ट्र की बदली राजनीति के पीछे के सटीक कारण

1. स्थानीय मुद्दे और क्षेत्रीय अस्मिता

यह चुनाव मोदी के इर्द गिर्द केंद्रित नहीं था. 2014 और 2019 में मोदी लहर थी. अकेले नरेंद्र मोदी फैक्टर के कारण ही कई नए उम्मीदवार भी चुने गए. पिछले चुनाव में राज्य के मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, स्थानीय समीकरण किसी भी तरह से प्रभावी नहीं थे. हालांकि इस चुनाव में महाराष्ट्र में मोदी की ऐसी लहर देखने को नहीं मिली. मोदी का करिश्मा नहीं दिखा. मोदी ने महाराष्ट्र में रिकॉर्ड रैलियां कीं लेकिन इसका नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ा. भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में चुनाव को मोदी बनाम राहुल गांधी बनाने की पूरी कोशिश की. कोल्हापुर की सभा में देवेन्द्र फडणवीस ने सीधे तौर पर कहा कि इस क्षेत्र में यह चुनाव शाहू महाराज बनाम संजय मांडलिक नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी है. बीजेपी ने चुनाव को मोदी केंद्रित बनाने की कोशिश की लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली.

2. शरद व उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति

दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि पार्टियों को तोड़ना बीजेपी के विरोध मे चला गया. चाहे वह शिवसेना में फूट हो या उसके बाद एनसीपी में फूट, दोनों ही फूट से बीजेपी को कोई खास फायदा नहीं हुआ. इसके विपरीत मतदाताओं में इस विभाजन को लेकर नाराजगी देखी गई. जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की शिवसेना को कमजोर किया गया और शरद पवार की एनसीपी में तोड़फोड़ मचाई गई, उसे भी जनता ने स्वीकार नहीं किया. आम लोगों की सहानुभूति उद्धव और शरद पवार के साथ थी. चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने ख़ुद शरद पवार और उद्धव ठाकरे की व्यक्तिगत तौर पर आलोचना की थी. मोदी ने भटकती आत्मा, नक़ली बच्चा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया. लेकिन यह आलोचना पवार-ठाकरे के प्रति सहानुभूति बढ़ाने वाली साबित हुई.

3. महाराष्ट्र में किसानों का रोष

पिछले कुछ महीनों से महाराष्ट्र में किसानों का गुस्सा साफ़ नज़र आ रहा था. उत्तर महाराष्ट्र में प्याज का मुद्दा छाया रहा. मराठवाड़ा और विदर्भ में कपास और सोयाबीन के मुद्दे पर चर्चा हुई. प्याज के मुद्दे को सीधे तौर पर महागठबंधन पर चोट के तौर पर देखा जा रहा था. निर्यात प्रतिबंध के खिलाफ किसानों में भारी गुस्सा था. बीजेपी इस रोष को कम करने में ख़ास कामयाब नहीं हो पाई है. उर्वरकों की बढ़ी कीमतें राज्य भर के किसानों के लिए एक प्रमुख मुद्दा बन गईं.

4. सोशल इंजीनियरिंग, मराठा-दलित-मुस्लिम एकसाथ

मराठा-दलित-मुस्लिम की सोशल इंजीनियरिंग में महाविकास अघाड़ी सफल रही. आरक्षण के लिए मराठा आंदोलन का सीधा फ़ायदा महाविकास अघाड़ी को हुआ. महायुति के उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ मनोज जारंग का रुख़ महाविकास अघाड़ी के फ़ायदे मे रहा. महाविकास अघाड़ी मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ़ करने में सफल रही. संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा होने के कारण बहुसंख्यक दलित मतदाता भी महाविकास अघाड़ी के पीछे एकजुट हैं. महायुति इस सोशल इंजीनियरिंग का प्रभावी ढंग से मुक़ाबला नहीं कर सकी.

5. विपक्ष का एकजुट रहना

इस चुनाव में वंचित और एएमआईएम का प्रभाव नहीं दिखा. वंचित बहुजन अघाड़ी स्वतंत्र रूप से लड़ रही थी, इसलिए महाविकास अघाड़ी को वोटों के विभाजन की चुनौती का सामना करना पड़ रहा था. 2019 के चुनावों में वंचित बहुजन अघाड़ी और एएमआईएम द्वारा लिए गए वोटों के कारण कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस के उम्मीदवार हार गए. लेकिन इस चुनाव में वंचित बहुजन अघाड़ी को ख़ास वोट नहीं मिले. ओवैसी की पार्टी को औरंगाबाद छोड़कर अन्य जगहों पर वोट नहीं मिले, महाविकास अघाड़ी को इसका भी फ़ायदा हुआ. इसके साथ ही महाविकास अघाड़ी एकजुट नज़र आई और कांग्रेस-ठाकरे ग्रुप और पवार ग्रुप के वोट एक-दूसरे को ट्रांसफर हो गए. यह मुद्दा महाविकास अघाड़ी के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ. इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस लोकसभा चुनाव के नतीजे आगामी विधानसभा चुनावों के साथ-साथ स्थानीय निकाय चुनाव में राज्य की राजनीति पर बड़ा प्रभाव डालेंगे.

लोकसभा चुनाव 2024: बीजेपी दक्षिण भारत में भगवा फहराने में सफल रही?

शारदा वी

अठारहवीं लोकसभा चुनाव के नतीजे दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देते हैं. दक्षिण भारत में कमजोर माने जाने वाली बीजेपी ने इस बार कर्नाटक और तेलंगाना के साथ आंध्र प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया है.

यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के गढ़ कहे जाने वाले केरल में भी बीजेपी ने पहली बार एक सीट जीत कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है. हालांकि तमिलनाडु बीजेपी के लिए काफी चैलेंजिंग रहा. तमिलनाडु में आक्रामक चुनाव प्रचार के बाद भी बीजेपी और उसके सहयोगी दल एक भी सीट नहीं जीत सके.

तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम(डीएमके) के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन ने राज्य की सभी 39 सीटें जीती है. गठबंधन ने केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की एकमात्र सीट पर भी जीत दर्ज की है.

कांग्रेस ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे. इन सभी दस सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है.

चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई बार तमिलनाडु पहुंचे.

लेकिन इसके बाद भी बीजेपी राज्य में एक सीट भी नहीं जीत सकी. हालांकि बीजेपी राज्य के 10 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही.

वरिष्ठ पत्रकार अरुण जनार्दन कहते हैं, "इस बार भाजपा के वोट शेयर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि पार्टी ने राज्य में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा है. हालांकि, पार्टी और उसके बड़े नेताओं के काफ़ी प्रयास के बाद भी बीजेपी राज्य में छाप छोड़ने में सफल नहीं रही."

बीजेपी के पूर्व सहयोगी अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) ने राज्य के क़रीब 29 सीटों पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है. वहीं, दूसरे लोकसभा सीटों पर पार्टी तीसरे और चौथे स्थान पर रही.

एआईएडीएमके की पूर्व अध्यक्ष और सीएम जयराम जयललिता का निधन 2016 में हुआ था.

राज्य की दूसरी बड़ी पार्टी जयललिता के निधन के बाद लगातार तीसरी बार हार का सामना कर रही है. फ़िलहाल पार्टी का पूरा ध्यान 2026 में होने वाली विधानसभा चुनाव पर है.

एआईएडीएमके ने 2014 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 39 में से 37 सीटें जीती थीं.

वहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन ने राज्य के सभी 39 सीटें जीती थीं.

बीजेपी ने कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से करीब 17 सीटें हासिल कर राज्य में अपना दबदबा बरकरार रखा है. पार्टी ने 2019 में 28 में से 25 सीटें जीती थीं. पिछली चुनाव के मुकाबले राज्य में बीजेपी की सीटें कम हुई हैं. ग्यारह महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बड़ा झटका था. कांग्रेस ने कर्नाटक में अकेले बहुमत के साथ सरकार बनाई थी. ऐसे समय में, जब यह माना जा रहा था कि भाजपा राज्य में अपनी पकड़ खो रही है, लेकिन बीजेपी ने खुद को राज्य में कायम रखा है.

वरिष्ठ पत्रकार विजय ग्रोवर कहते हैं, "कर्नाटक में चुनाव हमेशा जाति के इर्द-गिर्द घूमता है. पिछले विधानसभा चुनाव में प्रमुख लिंगायत समुदाय से आने वाले बीएस येदियुरप्पा को दरकिनार कर दिया गया था. बीजेपी को इसका परिणाम भुगतना पड़ा."

"इससे सबक सीखते हुए बीजेपी ने येदियुरप्पा को कर्नाटक का प्रदेश अध्यक्ष बनाया. इससे पार्टी को 2024 लोकसभा चुनाव में फायदा मिला है. हालांकि बीजेपी के एमपी राज्य में कोई भी विकास परियोजना लाने में विफल रहे." विजय ग्रोवर बताते हैं, "कांग्रेस ने पांच गारंटी देने का वादा किया था, जिसे उन्होंने अपनी सरकार के पहले एक साल में पूरा कर दिया. कांग्रेस के पास पूरा करने के लिए कोई और वादा नहीं बचा था."

"उच्च वर्ग और उत्तर भारतीय आबादी वाले शहरी लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा ने 2 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है. तटीय कर्नाटक में भाजपा धर्म के आधार पर वोट बैंक का ध्रुवीकरण करने में सक्षम रही. यहां लोगों ने जाति पर नहीं बल्कि हिंदू और मुस्लिम के तौर पर वोट किया." भाजपा की सहयोगी दल जनता दल (सेक्युलर) ने दो सीटें जीत कर भाजपा की स्थिति को और मजबूत कर दिया है.

25 लोकसभा सीटों वाली आंध्र प्रदेश ने एनडीए के पक्ष ने भारी जनादेश दिया है. यहां एनडीए को 21 सीटें मिली हैं. इससे पता चलता है कि वाईएसआर कांग्रेस के समर्थन में कमी आई है. यह राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में व्यापक बदलाव

को दर्शाता है.

भाजपा सहयोगी और पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) ने राज्य की 16 सीटों पर जीत दर्ज की है. वहीं, भाजपा को तीन और गठबंधन के दूसरे सहयोगी जन सेना पार्टी (जेएसपी) को राज्य में दो सीटें मिली हैं.

वरिष्ठ पत्रकार सुमित भट्टाचार्य कहते हैं, "आंध्र प्रदेश में कोई मोदी फैक्टर नहीं है. वहां के लोग वाईएसआर कांग्रेस से नाखुश थे. आंध्र में टीडीपी को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सत्ता विरोधी वोट मिले हैं. बीजेपी को इस चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिला है. इस जीत से चंद्रबाबू को भाजपा से निगोशिएट करने में मदद मिलेगी."

उन्होंने कहा, "साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जो हुआ, यह उसका उल्टा है. यह ध्यान देने वाली बात है कि पवन कल्याण की जेएसपी ने 2 लोकसभा और 21 विधानसभा सीटों चुनाव लड़ा था. उनकी पार्टी इन सभी सीटों पर जीत हासिल की है."

तमिलनाडु के राजनीति विज्ञान के जाने माने प्रोफेसर रामू मणिवन्नन कहते हैं, "नतीजों से पता चलता है कि बीजेपी ने दक्षिण में अपनी छाप छोड़ी है. पार्टी को अकेले बहुमत नहीं मिलने की वजह से सरकार बनाने के लिए दक्षिणी राज्यों सहित अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना होगा."

"भाजपा अब दक्षिण विरोधी पार्टी नहीं रह सकती. लोग स्थिर सरकार को सत्तावादी सरकार के रूप में समझते हैं, जो ग़लत है. हम एक अच्छी सरकार चाहते हैं."

» तमिलनाडु के राजनीति विज्ञान के जाने माने प्रोफेसर रामू मणिवन्नन कहते हैं, "नतीजों से पता चलता है कि बीजेपी ने दक्षिण में अपनी छाप छोड़ी है. पार्टी को अकेले बहुमत नहीं मिलने की वजह से सरकार बनाने के लिए दक्षिणी राज्यों सहित अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना होगा."

तेलंगाना में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिली. बीजेपी और कांग्रेस ने 17 लोकसभा सीटों वाले राज्य में 8-8 सीटें जीती हैं. पिछली बार की तुलना में बीजेपी को तेलंगाना में 4 सीटें ज्यादा मिली हैं.

एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से लगातार पांचवीं बार सांसद बने हैं.

ये चुनाव पारंपरिक रूप से भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के प्रभुत्व वाले तेलंगाना में बदलाव का संकेत है. बीआरएस को पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के नाम से जाना जाता था.

वरिष्ठ पत्रकार एमवीए शास्त्री कहते हैं, "कई लोकसभा सीटों पर बीआरएस के वोट बीजेपी के खाते में गए हैं और तेलंगाना इसका गवाह बना है. मलकाजगिरी में भाजपा उम्मीदवार एटाला राजेंद्रन ने अच्छी बढ़त जीत दर्ज की है. वे टीआरएस की सरकार में मंत्री रह चुके हैं."

वे कहते हैं कि "जय श्री राम के नारे और मोदी के करिश्मे के साथ बीजेपी के पास पहले से ही एक वोट बैंक है. बीआरएस के वोटों ने इसे और मजबूत किया है. बीआरएस जिसके पास लगभग 35 फीसदी वोट शेयर है, इस बार कम हुआ है." केरल में एग्जिट पोल की भविष्यवाणी सही साबित हुई. केरल, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ का गढ़ साबित हुआ. यह राज्य दो पक्षीय चुनाव के लिए जाना जाता है. यहां यूडीएफ और एलडीएफ के बीच मुकाबला होता है. इस बार कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने अधिकतर सीटें जीती हैं.

बीजेपी को पहली बार केरल में एक सीट मिली है. अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी ने त्रिशूर लोकसभा क्षेत्र से 70,000 से अधिक वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की है. सत्ताधारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ एक सीट जीतने में कामयाब हो पाई. सीपीएम उम्मीदवार ने अलाथुर में 20,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है.

वरिष्ठ पत्रकार अरुण जनार्दनन कहते हैं, "इस बार केरल में सत्ता विरोधी लहर और दिल्ली में कांग्रेस का महत्व दो मुख्य फैक्टर थे. केरल में हिंदू आबादी 50 फीसदी से ज़्यादा है. अल्पसंख्यक ख़ासकर मुस्लिम परंपरागत रूप से कांग्रेस को वोट देते रहे हैं."

"सत्तारूढ़ सीपीएम भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रही है और पिनाराई विजयन की सरकार और पार्टी पर पूरी पकड़ है. करीब 12 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के उम्मीदवारों ने एक लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की है."

बंगाल में मोदी की गारंटी पर भारी पड़े ममता के वादे

प्रभाकर मणि तिवारी

पश्चिम बंगाल देश के उन चुनिंदा राज्यों में है जहां बीजेपी को अपनी सीटों में वृद्धि की उम्मीद थी. लेकिन नतीजे इससे काफी अलग रहे. पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के तमाम नेताओं ने अपने चुनाव अभियान में दूसरे मुद्दों के साथ ही मोदी की गारंटी को प्रमुख मुद्दा बनाया था. इसकी काट के तौर पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने ममता की गारंटी शुरू की थी जिसके तहत सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रचार किया गया. नतीजों से साफ हो गया है कि मोदी की गारंटी पर ममता के वादे भारी साबित हुए हैं. यही वजह है कि भाजपा यहां पिछली बार जीती हुई अपनी सीटों को भी बचाने में नाकाम रही है.

चुनावी नतीजों ने यह भी बताया है कि तमाम कोशिशों के बावजूद तृणमूल कांग्रेस का महिला और अल्पसंख्यक वोट बैंक अटूट रहा है. बंगाल में टीएमसी का यह दूसरा बेहतरीन प्रदर्शन है. इससे पहले वर्ष 2014 में उसने 34 सीटें जीती थी.

पश्चिम बंगाल देश के उन चुनिंदा राज्यों में है जहां बीजेपी को अपनी सीटों में वृद्धि की उम्मीद थी. राज्य की 42 सीटों में से 18 उसके पास पहले से ही थी. उसने बाकी 24 में से कम से कम दस सीटें जीतने की रणनीति के साथ अपना चुनाव अभियान शुरू किया था. इसके लिए उसे चुनाव से पहले ही संदेशखाली जैसा एक ठोस मुद्दा भी हाथ लग गया था. उसके बाद बीजेपी संदेशखाली में महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न को अपने सियासी हित में भुनाने के लिए आक्रामक होकर मैदान में कूद पड़ी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने भी इस मामले में पूरा सहयोग दिया और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को इस मामले में आंदोलन की खुली छूट दे दी.

खुद प्रधानमंत्री भी चुनाव की तारीख तय होने से पहले ही बंगाल के दौरे पर आए और संदेशखाली की कुछ कथित पीड़िताओं से मुलाकात कर उनको शक्तिस्वरूपा बताया था. उसके बाद शुभेंदु की सिफारिश पर उनमें से ही एक रेखा पात्रा को पार्टी ने बशीरहाट सीट पर अपना उम्मीदवार बना दिया. संदेशखाली इसी संसदीय क्षेत्र में है. दरअसल, बीजेपी इस मुद्दे के बहाने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए ममता के मजबूत महिला वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती थी.

लेकिन एक स्टिंग वीडियो के सामने आने के बाद पूरा मामला ही बदल गया. उस वीडियो में बीजेपी के एक स्थानीय नेता ने बताया था कि यह पूरी घटना फर्जी है और किसी भी महिला के साथ रेप या यौन उत्पीड़न की घटना नहीं हुई. इस पूरे मामले के पीछे बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी का हाथ बताया गया था. उसके बाद ममता बनर्जी ने इसे हाथों-हाथ लेते हुए इसे बंगाल की महिलाओं की अस्मिता के साथ जोड़ दिया. वो इस बात का प्रचार करने लगी कि बीजेपी के नेताओं की निगाह में बंगाल की महिलाओं की अस्मत की कोई कीमत नहीं है. इसका असर ममता के मजबूत महिला वोट बैंक पर हुआ.

भाजपा को बंगाल में जिस नागरिकता संशोधन कानून से सबसे ज्यादा उम्मीद थी वह भी पूरी तरह फेल रहा. राज्य में एक करोड़ से ज्यादा मतुआ वोटर कई सीटों पर मतुआ वोटर निर्णायक हैं. उनको ध्यान में रखते हुए ही पार्टी ने यहां चुनाव से ठीक पहले इस कानून को लागू किया था. इसके उलट ममता बनर्जी इस कानून का इस्तेमाल अपने सियासी हित में करती रहीं. वो शुरू से ही कहने लगी कि बंगाल में किसी भी कीमत इस कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा. ममता और पार्टी के दूसरे नेता अपनी रैलियों में लगातार कहते रहे कि इस कानून के बाद ही भाजपा सरकार नेशनल रजिस्टर आफ सिटीजंस (एनआरसी) ले आएगी और उसके बाद तमाम लोगों को घुसपैठिया साबित कर देश से खदेड़ दिया जाएगा. परस्पर विरोधी दावों के कारण इस कानून पर भ्रम की स्थिति पैदा होने की वजह से यह मुद्दा चुनाव में बेअसर साबित हुआ.

42 सीटों के लिए कई चरणों में और काफी देर से उम्मीदवारों की सूची जारी करने और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष जैसे नेताओं की जीती हुई सीट बदलना भी भाजपा के लिए महंगा साबित हुआ. इसके विपरीत ममता बनर्जी ने 10 मार्च को कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित रैली में एकमुश्त सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी थी. इससे पार्टी को अपनी रणनीति बनाने और उसके तहत प्रचार के लिए बीजेपी के मुकाबले ज्यादा समय मिल गया. प्रदेश बीजेपी नेताओं में नए बनाम पुराने नेताओं के विवाद ने भी पार्टी की लुटिया डुबोने में अहम भूमिका निभाई है.

कांग्रेस के साथ तालमेल के तहत

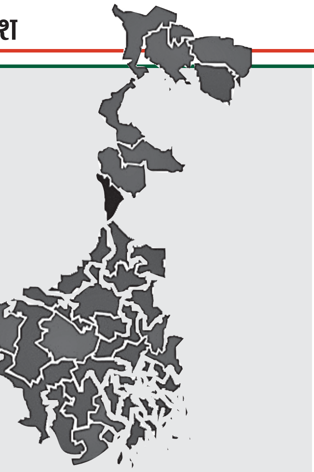

मैदान में उतरने वाली सीपीएम को इस बार भी कोई सीट नहीं मिली. उसके प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम मुर्शिदाबाद सीट पर हार गए. कांग्रेस को भी एक सीट का नुकसान उठाना पड़ा है.

कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका बंगाल की बहरामपुर सीट पर लगा है. वहां टीएमसी उम्मीदवार और हरफनमौला क्रिकेटर यूसुफ पठान ने लगातार पांच बार यह सीट जीतने वाले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया है.

पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन : जहां तक पूर्वोत्तर का सवाल है, मणिपुर में बीजेपी को बीते साल से जारी जातीय हिंसा का खामियाजा भुगतना पड़ा है. वहां एक सीट उसके पास थी और एक उसकी सहयोगी के पास. लेकिन दोनों सीटें उसके हाथ से निकल गई हैं. अरुणाचल प्रदेश में पार्टी ने विधानसभा में बहुमत पाने के साथ ही लोकसभा की दोनों सीटें भी जीत ली हैं. लेकिन इसमें कुछ अप्रत्याशित नहीं है. वहां विपक्ष के बिखराव ने उसकी राह आसान कर दी थी. राज्य में मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत दस विधायक तो पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए थे. त्रिपुरा में भी पार्टी की जीत अप्रत्याशित नहीं है. इलाके के सबसे बड़े राज्य असम में पार्टी की स्थिति में खास बदलाव की उम्मीद नहीं है. पिछली बार उसने यहां नौ और इलाके की 25 में से 14 सीटें जीती थी. इस बार वह इसी आंकड़े के आसपास नजर आ रही है.

बीजेपी बंगाल के पड़ोसी ओडिशा में विधानसभा चुनाव में जीत को राहत मान सकती है. लेकिन वहां कई कारकों ने उसकी जीत में अहम भूमिका निभाई है. लोकसभा चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा है. चुनाव नतीजों से पता चलता है कि ओड़िया अस्मिता को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाने का बीजेपी का फैसला हिट हो गया है. राज्य के लोगों ने बीजू जनता दल (बीजद) में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के करीबी वी. के. पांडियन की बढ़ती भूमिका के खिलाफ वोट दिया है.

राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर समीरन पाल कहते हैं, "राज्य के लोगों ने एक बार फिर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर ही भरोसा जताया है. संदेशखाली, भर्ती घोटाला और नागरिकता संशोधन कानून जैसे भाजपा के मुद्दे पूरी तरह बेअसर साबित हुए हैं. इसके अलावा धार्मिक ध्रुवीकरण का उसका प्रयास पहले की तरह इस बार भी बेअसर रहा. यह चुनाव मोदी बनाम ममता था और इसमें वर्ष 2021 की तरह बाजी एक बार फिर ममता के हाथ ही रही है."

उत्तर प्रदेश में कैसे बिखर गई बीजेपी?

*समीरात्मज मिश्र

सियासी लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है. यहां कांग्रेस और एसपी के गठबंधन की आंधी में कई दिग्गज उड़ गए. आखिर यूपी में ऐसा क्या हुआ? यूपी में एसपी 36 सीटें जीत चुकी है और एक सीट पर बढ़त बनाए हुए है. इस सीट पर भी शीर्ष दो उम्मीदवारों में इतना अंतर है कि रुझान नतीजे में ही बदलेगा. वहीं इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टी कांग्रेस यूपी में छह सीटें जीतने में कामयाब रही.

2019 के चुनाव में एसपी ने पांच और कांग्रेस ने महज एक सीट जीती थी. इस बार एसपी ने यूपी में 62 कांग्रेस ने 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. वहीं 2019 में 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने इस बार 33 सीटें जीती हैं. यानी 2019 की तुलना में लगभग आधी.

एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर जनता का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, "जनता को प्रणाम, जनमत को सलाम! यूपी की जागरूक जनता ने देश को एक बार फिर से नई राह दिखाई है, नई आस जगाई है." इंडिया गठबंधन के बारे में अखिलेश ने कहा, "यह इंडिया गठबंधन और पीडीए की एकता की जीत है. सबको हृदय से धन्यवाद, दिल से शुक्रिया!"

कौन से मंत्री नहीं बचा पाए अपनी सीटें

यूपी में इंडिया गठबंधन की इस आंधी में बीजेपी के कई दिग्गज नेता उड़ गए. इनमें वे नेता भी हैं, जो पिछले चुनाव में भारी अंतर से जीते थे. यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट पर महज डेढ़ लाख वोटों से जीत दर्ज कर पाए. यह वाराणसी से उनका तीसरा चुनाव था और तीनों चुनावों में यह जीत का सबसे कम अंतर है. बीजेपी के कई मंत्री भी चुनाव हार गए. इनमें सबसे अहम हार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की रही, जिन्हें अमेठी में कांग्रेस उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा ने 1.60 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराया.

वहीं रायबरेली में राहुल गांधी ने बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह को करीब चार लाख वोटों से हराया. लखनऊ में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह एक लाख वोटों के अंतर से जीत पाए, जबकि फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति, खीरी से अजय मिश्र टेनी, मोहनलालगंज से कौशल किशोर, चंदौली से महेंद्र नाथ पांडेय, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान और जालौन से भानुप्रताप सिंह जैसे केंद्रीय मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है.

राजनाथ सिंह के अलावा मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल, आगरा से एसपी सिंह बघेल और महाराजगंज से पंकज चौधरी ही ऐसे केंद्रीय मंत्री रहे, जो अपनी सीटें बचाने में कामयाब हुए. वहीं एसपी के प्रमुख अखिलेश यादव के अलावा उनकी पत्नी डिंपल यादव और आजमगढ़ से उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव भी चुनाव जीतने में कामयाब रहे.

यह स्थिति तब है, जब अलग-अलग एक्जिट पोल बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को यूपी 70 से भी ज्यादा सीटें दे रहे थे. लेकिन, इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने उन सारे एक्जिट पोल को नकार दिया और अपने समर्थकों से नतीजों इंतजार करने को कहा. साथ ही, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को यह हिदायत भी दी कि स्ट्रॉन्ग रूम की रखवाली की जाए और किसी भी अप्रिय स्थिति की आशंका पर नजर रखी जाए.

बड़ी हैरानी की बात यह रही कि अयोध्या में बना भव्य राम मंदिर इस लोकसभा चुनाव में मुद्दा नहीं बन पाया और बीजेपी को पिछली सफलता हासिल करने जितने वोट नहीं दिला पाया. जबकि 1980 के दशक में बीजेपी के गठन के समय से ही यह उसका चुनावी मुद्दा रहा है. बीजेपी को उम्मीद थी कि मंदिर बन जाने का उसे सीधा लाभ मिलेगा, जबकि स्थिति यह रही कि अयोध्या शहर जिस फैजाबाद लोकसभा सीट के तहत आता है, उस सीट पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा. बीजेपी के मौजूदा सांसद लल्लू सिंह को सपा के अवधेश प्रसाद ने मात दी है.

यही नहीं, अवध के इलाके की कई अन्य सीटें भी इंडिया गठबंधन जीतने में कामयाब रहा. हां, बहुचर्चित कैसरगंज सीट बीजेपी ने जरूर जीत ली, जहां मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह बीजेपी के उम्मीदवार थे.

चुनाव में बीजेपी ने राम मंदिर और हिंदू-मुसलमान जैसे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दिया, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने रोजगार, महंगाई, शिक्षा और पेपर लीक जैसे मुद्दों को हवा दी. कांग्रेस के सत्ता में आते ही अग्निपथ योजना खत्म करने जैसे वादों ने भी युवाओं को गठबंधन के प्रति आकर्षित किया.

इसके अलावा चुनाव में बीएसपी के लगभग गैर-मौजूद रहने ने भी इस बार इंडिया गठबंधन को काफी मदद पहुंचाई. यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के नेतृत्व वाली बीएसपी 80 में से एक भी सीट पर कोई खास वोट हासिल नहीं कर पाई, जीतना तो दूर की बात है.

बीएसपी के मतदाताओं ने बीजेपी के खिलाफ उन आशंकाओं के चलते इंडिया गठबंधन को वोट दिया कि यदि बीजेपी दोबारा बहुमत के साथ सत्ता में आई, तो वह 'संविधान बदल देगी'. इस मुद्दे को इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने तो जोर-शोर से उठाया ही. आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर रावण ने भी इसे मुद्दा बनाया और इसी के बूते उन्होंने नगीना सीट बड़े अंतर से जीत ली. इस सीट पर बीएसपी उम्मीदवार को चौथे नंबर पर संतोष करना पड़ा.

नवीन पटनायकः भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक रहे सीएम की विदाई

बीते 24 साल तक चुनावों में अजेय रहने वाले नवीन पटनायक को ओडिशा में भारी हार का सामना करना पड़ा है. वो उस बीजेपी से हार गए, जिसने 90 दशक में ओडिशा की राजनीति में उनके प्रवेश का समर्थन किया था. ओडिशा में लोकसभा के साथ कराए गए विधानसभा चुनावों के नतीजों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है. उसे विधानसभा की 147 सीटों में 78 और लोकसभा की 21 सीटों में 20 पर जीत मिली हुई है. अब पार्टी पहली बार इस प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी. नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल ने विधानसभा चुनावों में 51 सीटों पर जीत दर्ज की और लोकसभा में शून्य पर रही. नवीन बाबू ख़ुद उन दो सीटों में से एक पर हार गए, जहाँ उन्होंने चुनाव लड़ा था. साल 2019 में बीजेडी ने 117 विधानसभा सीटें और 12 लोकसभा सीटें जीती थीं. साल 2008 में बीजेपी, बीजेडी से अलग हो गई थी और उसके बाद कई सालों तक उसे कोई ख़ास क़ामयाबी नहीं मिली. लेकिन 2019 में उसने ओडिशा में लोकसभा की 8 सीटें जीतीं.

जबकि एक साथ कराए गए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 23 सीटें मिली और कांग्रेस को तीसरे नंबर पर धकेलते हुए प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी.

इस बात को ध्यान में रखते हुए नवीन पटनायक ने अपने पांचवें कार्यकाल में सांस्कृतिक राजनीति का सहारा लेना शुरू किया. इस बात का अहसास करते हुए कि छोटे कस्बों और शहरों में आकांक्षी और युवा मतदाताओं का एक वर्ग बीजेपी का समर्थन कर रहा है, नवीन ने कल्याणकारी स्कीमों से आगे देखना शुरू किया, जो कि उनकी राजनीतिक का केंद्र बन गया था.

मतदाताओं के इस नए वर्ग को साथ लाने के लिए, बीजेडी सरकार ने ओडिशा को भारत का एक स्पोर्ट्स कैपिटल के रूप में पेश करने की कोशिश की. क्रिकेट से परे अन्य खेलों को बढ़ावा दिया जैसे कि हॉकी वॉलीबॉल और बैडमिंटन.

राज्य सरकार पुरुष और महिला नेशनल हॉकी टीमों को प्रायोजित करती रही है. इसने राज्य में बड़े धूमधाम और दिखावे के साथ दो हॉकी वर्ल्ड कप सिरीज़ का भी आयोजन किया.

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद बीजेपी के प्रति बढ़ते झुकाव का मुकाबला करने के लिए बीजेडी सरकार ने पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के आसपास एक हेरिटेज कॉरिडोर का निर्माण कराया. साथ ही पूरे ओडिशा में सभी प्रमुख मंदिरों का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण कराया. इस साल के शुरू में राज्य सरकार ने राज्य के साहित्य और साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए पहला विश्व ओड़िया भाषा सम्मेलन आयोजित किया. सरकार ने बड़े पैमाने पर सरकारी स्कूलों के इन्फ्रास्ट्रक्चर, बस सेवाओं, टर्मिनल और अस्पतालों के आधुनिकीकरण का काम भी शुरू कराया.

हालांकि उनके एक रणनीतिक चूक हो गई. कोई भी राजनेता इन परियोजनाओं की निगरानी करते हुए खुद श्रेय लेता लेकिन नवीन ने सब कुछ अपने प्रमुख सहयोगी और नौकरशाह वीके पांडियन को सौंप दिया, जो प्रशासन का चेहरा बन गए और अंत में सीएम से भी अधिक ताकतवर दिखाई दिए.

नवीन ऐसे राजनेता हैं, जो अपने आसपास किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की इजाज़त नहीं देते. उन्होंने हमेशा ही अपने प्रशासन का सार्वजनिक चेहरा बनने के लिए नौकरशाहों पर भरोसा किया. जब वो पहली बार सत्ता में आए, नवीन के दाएं हाथ थे, पूर्व नौकरशाह प्यारी मोहन मोहपात्रा, जिन्होंने 12 साल तक वफादारी से सेवा करते हुए सीएम के खिलाफ तख़्तापलट की कोशिश की थी. तख़्तापलट की कोशिश फेल हो गई और नवीन पटनायक ने उन्हें राजनीतिक वनवास में भेज दिया. ये देखते हुए कि राजनीति में आया ओड़िया नौकरशाह भी उनकी गद्दी छीन सकता था, उन्होंने एक ग़ैर ओड़िया आईएएस अफ़सर वीके पांडियन को चुना. इस फैसले ने छोटे छोटे असंतोषों की एक पूरी श्रृंखला की शुरुआत की, जिसकी क़ीमत नवीन को अपना मुख्यमंत्री पद गंवाकर चुकानी पड़ी.

पिछले एक दशक में सरकार और पार्टी में पांडियन का दबदबा बढ़ता रहा, जिसके कारण विपक्ष को ये कहने का मौका मिला कि वही प्रशासन के असली मुखिया हैं.

जब पांडियन ने सेवा से इस्तीफ़ा दिया, बीजेडी में शामिल हुए और 2024 चुनावों में प्रचार करना शुरू किया तो बीजेपी ने अपने प्रचार अभियान का उन्हें ही केंद्रीय मुद्दा बना दिया.

बीजेपी का कहना था कि तमिलनाडु के होने के बावजूद पांडियन संभवतः नवीन के बाद सीएम बनेंगे, यह ओड़िया अस्मिता का अपमान है.

यहां तक कि पीएम मोदी ने ओडिशा में अपने कुछ भाषणों में सीधे इस मुद्दे का जिक्र किया. नवीन को एक साक्षात्कार में स्पष्टीकरण देने पड़ा कि पांडियन उनके उत्तराधिकारी नहीं बनने जा रहे हैं. लेकिन यह सफ़ाई थोड़ी देर से आई. नवीन पटनायक की हार का प्रमुख कारण केवल पांडियन नहीं हैं, बल्कि तमिल पहचान वो झटका था जिसने नवीन के ओडिशा के किले को ढहा दिया. शिक्षा और स्वास्थ्य में बीजेडी सरकार का रिकॉर्ड कथित रूप से बहुत अच्छा नहीं रहा.

संसद में केंद्र सरकार की ओर से पेश आंकड़ों के अनुसार, 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों के मामले में ओडिशा शीर्ष राज्य है. 2021-22 में राष्ट्रीय औसत 20.6% था जबकि ओडिशा की दर 49.9% थी. हालांकि पिछले पांच साल में सरकार ने सरकारी स्कूलों को सुधारने की महात्वाकांक्षी शुरुआत की लेकिन स्मार्ट क्लासरूम और उपकरण अध्यापकों की कमी और शिक्षा की ख़राब गुणवत्ता की कमी को पूरा नहीं कर सकता. केंद्र के आयुष्मान भारत को काउंटर करने के लिए बीजेडी सरकार ने लगभग सभी के लिए बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना जैसी स्वास्थ्य बीमा प्रोग्राम की शुरुआत की.

हालांकि रिपोर्टों में यह योजना सफ़ल है लेकिन राज्य स्तर के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में अच्छे डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की कमी को यह योजना पूरा नहीं कर सकती. पूरे प्रदेश में प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य व्यवस्था की बुरी हालत है. कम रोज़गार चिंता का विषय बना हुआ है. आईएलओ और इंस्टीट्यूट ऑफ़ ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में शिक्षित युवाओं में सर्वाधिक बेरोज़गारी है. बीजेडी सरकार ने श्रम केंद्रित आर्थिक गतिविधियों के लिए सुविधा नहीं दी, जैसे कि टेक्सटाइल उद्योग और फ़ूड प्रोसेसिंग.

प्रशासन की इन ख़ामियों के अलावा खनन और चिट फ़ंड में भ्रष्टाचार के बढ़ते आरोपों, स्थानीय नेताओं की गुंडागर्दी और कल्याणकारी योजनाओं में निष्पक्ष आवंटन में विफलता ने बीजेडी के ख़िलाफ़ 24 साल से जमा हो रही सत्ता विरोधी लहर को और मजबूत किया. हालांकि नवीन की निजी लोकप्रियता पार्टी और सरकार के ख़िलाफ़ असंतोष पर काबू पाने में कामयाब रही.

सन 2000 तक बीजेपी को ओडिशा में शासन का मौका नहीं मिला था. उसके बाद से लेकर 2009 तक उसने बीजेडी के साथ मिलकर गठबंधन सरकार चलाई. तब अटल बिहारी वाजपेयी और एलके आडवाणी की अगुवाई वाली बीजेपी ने कई कारणों से नवीन पटनायक को गठबंधन का पार्टनर बनाया. वो बीजू पटनायाक के बेटे थे, जिनका कद ओड़िया लोगों में एक कल्ट बन गया था. पायलट के रूप में वो कई संघर्ष वाले देशों में बचाव मिशन पर जा चुके थे, जैसे इंडोनेनशिया. बीजू बाबू के प्रति लोगों में उत्सुकता थी. औद्योगिकरण के मार्फ़त ओडिशा की अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने की उनकी कोशिशों को शिक्षित ओड़िया लोगों की ओर से सराहना मिली. केवल सात साल तक सीएम रहने के बावजूद बीजू बाबू के व्यवहार और दिलेरी ने लोगों के बीच प्यार और प्रशंसा दिलाई. ओडिशा के इतिहास में उनके अलावा ऐसा कोई सीएम नहीं रहा जिसके किस्से आज भी जनता के बीच बड़े प्यार से सुनाए जाते हों.

बीजू पटनायक कांग्रेस के कद्दावर नेता थे. वो जवाहरलाल नेहरू के पसंदीदा थे. लेकिन इंदिरा गांधी के ज़माने में पार्टी से अलग हो गए और ओडिशा में कांग्रेस विरोधी राजनीति की धुरी बन गए. उन्होंने कांग्रेस को हराया और 1990 से 1995 के बीच मुख्यमंत्री रहे. कुर्सी से हटने के दो साल बाद जब 1997 में बीजू बाबू का देहांत हुआ उनके अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़ को देख दिल्ली के राजनीतिक लोग हैरान रह गए.

जल्द ही बीजू जनता दल का गठन हुआ और नवीन पटनायक पार्टी का चेहरा बने. बीजू पटनायक ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपने बच्चों को राजनीति में करियर बनाने को प्रोत्साहित नहीं किया. साल 2008 में स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती के मारे जाने के बाद हुए कंधमाल दंगे में कई ईसाई लोग मारे गए थे, जिसके बाद बीजेडी-बीजेपी गठबंधन में दरार पड़ गई. इसके बाद बीजेडी ने अकेले दम पर 2009, 2014 और 2019 में सरकारें बनाईं.

नवीन पटनायक की राजनीति में एक चीज अनोखी है, वो ये कि महिलाओं और आबादी के हाशिये पर रहने वाले लोगों पर फोकस. पहली बार सत्ता में आने पर उन्हें दो चीजें लगीं. पहली, ओडिशा ऐतिहासिक रूप से एक ग़रीब राज्य था, जहां ग़रीबी की जड़ें गहरी थीं. इसे सिर्फ औद्योगिकरण करने और नीचे तक इसके प्रभाव के जाने का इंतज़ार करते हुए हल नहीं किया जा सकता.

दूसरे, उन्होंने समझा कि ग़रीब घरों में महिलाओं और बुजुर्ग लोगों को सरकारी मदद की ज़्यादा ज़रूरत है.

24 सालों में नवीन बाबू ने सबसे ग़रीबों लोगों के लिए कल्याणकारी नीतियों का एक सुरक्षा चक्र बनाया. इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ममता स्कीम, जिसमें कथित रूप से 60 लाख गर्भवती महिलाओं और माओं को 2,900 करोड़ रुपये के बैंक ट्रांसफ़र से लाभ मिला. इस स्कीम ने बाल मृत्युदर की उच्च स्तर को कम करने में काफ़ी मदद की. एक और सफल स्कीम है मधु बाबू पेंशन योजना, जो वरिष्ठ नागरिकों के अलावा, विधवाओं, अनाथों, ट्रांसजेंडर समुदाय, एड्स और लेप्रोसी के मरीजों को भी कवर करती है. कोई आश्चर्य नहीं कि ग्रामीण ओडिशा में महिलाएं और बुजुर्ग लोग पटनायक को प्यार से 'बूढ़ा बेटा' कहते हैं. बीजेडी शायद भारत में एकमात्र राजनीतिक पार्टी है, जिसने लंबी अवधि में ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक हालात सुधारने के लिए व्यवस्थित रूप से ध्यान दिया.

गोवंश अभ्यारण योजना लाएगी विष्णु देव साय सरकार

रायपुरः सड़कों पर खुले में घूमने वाले स्वामी विहीन गौवंशों की सुरक्षा एवं दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए साय सरकार प्रदेश में गौवंश अभ्यारण्य योजना ले कर आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अधिकारियों को इस संदर्भ में कार्ययोजना बनाने के आवश्यक निर्देश दिए हैं। राज्य में पशुधन विकास विभाग, पंचायत, राजस्व एवं वन विभाग के समन्वय से गौवंश अभ्यारण्य संचालित करने की योजना है। इस योजना के क्रियान्वयन से सड़कों पर भूखे-प्यासे भटकने वाले गौवंश को न केवल नियमित आहार मिल सकेगा वरन् उनकी उचित देखभाल और चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध होगी। गौवंश अभ्यारण्य पशुधन के लिए उचित रहवासी वातावरण से परिपूर्ण होगा।

> इस योजना के क्रियान्वयन से सड़कों पर भूखे-प्यासे भटकने वाले गौवंश को न केवल नियमित आहार मिल सकेगा वरन् उनकी उचित देखभाल और चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध होगी।

गौरतलब है कि सड़कों पर घूम रहे स्वामी विहीन पशुधन न केवल यातायात के लिए बाधा बन रहे हैं वरन् आए दिन दुर्घटनाओं का कारण भी बनते हैं। भूख से बेहाल पशुधन द्वारा कूड़ा-कचरा एवं प्लास्टिक खाने से उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गौवंश अभ्यारण्य योजना इसे रोकने की दिशा में सकारात्मक कदम साबित होगी।

भ्रष्टाचार मुक्त, सेवा, सुरक्षा और संवर्धन होगा योजना का ध्येय वाक्य – विष्णु देव साय*

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि ठोस कार्ययोजना के माध्यम से भ्रष्टाचार मुक्त, सेवा, सुरक्षा और संवर्धन का ध्येय वाक्य ले कर प्रदेश में स्वामी विहीन पशुधन के लिए गौवंश अभ्यारण्य की रूप रेखा बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। प्रस्तावित योजना लागू होने पर न केवल सड़कों पर भूखे-प्यासे भटकने वाले गौवंशों को नियमित आहार, देखभाल और चिकित्सकीय सुविधा मिलेगी वरन् दुर्घटनाओं पर भी लगाम लगेगी।

एक बार फिर बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार

▪ मनीष कुमार

इस लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी के मुकाबले जेडीयू का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा. बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नीतीश बीजेपी के लिए मजबूरी बन चुके हैं, लेकिन अटकलें तेज हैं कि कहीं वह फिर न पलट जाएं.

बिहार के लोकसभा नतीजों से साफ हो गया है कि नीतीश कुमार का वोट बैंक उनके साथ मजबूती से खड़ा है. अति पिछड़ी जातियों और महिलाओं ने उन्हें एक बार फिर जमकर वोट दिया है. वहीं लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के वादों पर भी काफी हद तक एतबार जताया है.

उधर चार सीटें जीतकर लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी को संजीवनी तो मिल गई, किंतु तेजस्वी यादव की ताबड़तोड़ जनसभाओं का अपेक्षित परिणाम पार्टी को नहीं मिला. एम-वाई समीकरण भी दरकता हुआ नजर आया. प्रदेश की हॉट सीटों में शुमार पूर्णिया निर्दलीय, समस्तीपुर एलजेपी, सारण बीजेपी और काराकाट वाम दल के खाते में गई. पूर्णिया ऐसी सीट रही, जहां पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी इस उम्मीद के साथ कांग्रेस में विलय कर दी कि उन्हें वहां से टिकट मिल जाएगा. लेकिन बंटवारे में यह सीट आरजेडी के खाते में चली गई. फिर पप्पू यादव ने वहां से बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ा. उनका दावा था कि आरजेडी ने उन्हें टिकट देने का वादा किया था, लेकिन बाद में जेडीयू से आईं विधायक बीमा भारती को टिकट दे दिया गया.

इस बार आरजेडी ने 23 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे. लालू प्रसाद के लिए निजी तौर पर राहत की बात यह रही कि उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती लगातार दो लोकसभा चुनाव हारने के बाद पाटलिपुत्र सीट जीतने में कामयाब रहीं. यहां उन्होंने बीजेपी के रामकृपाल यादव को हराया. लेकिन, दूसरी ओर लालू को किडनी देने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य को सारण में बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी के हाथों हार का सामना करना पड़ा. रोहिणी के लिए लालू ने सारण में रहकर जोरदार प्रचार किया था. वहीं मीसा के लिए मोर्चा मां राबड़ी देवी ने संभाल रखा था. पर सारण में लालू का तिलिस्म बेटी की नैया पार नहीं लगा सका.

बिहार में इंडिया गठबंधन के अन्य सहयोगियों- कांग्रेस, वीआईपी और वामदलों का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा. हालांकि, उन्हें जितनी सीटों पर जीत मिली है, वह 2019 की तुलना में उपलब्धि ही मानी जाएगी. आरजेडी को पूरी चार, भाकपा-माले को दो और कांग्रेस को दो सीटों का फायदा हुआ है. पिछले आम चुनाव में एनडीए की 39 सीटों के मुकाबले विपक्ष से सिर्फ कांग्रेस ने इकलौती सीट किशनगंज से जीती थी.

इंडिया गठबंधन के एक अन्य सहयोगी मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी तीनों सीट पर पिछड़ गई. तेजस्वी ने मुकेश के साथ पूरे बिहार में खूब दौरे किए थे. उम्मीद थी कि मुकेश निषाद जाति के लोगों के वोट आरजेडी को दिलाने में कामयाब होंगे.

राजनीतिक समीक्षक अरुण कुमार चौधरी कहते हैं, ''जिन सीटों पर इस बार इंडिया गठबंधन को जीत मिली है, वहां कुछ न कुछ स्थानीय कारण प्रभावी रहे. जहानाबाद में अरुण कुमार के खड़े हो जाने के कारण वोट बंटा. बक्सर में अश्विनी चौबे का टिकट काटना और बाहरी प्रत्याशी थोपना महंगा पड़ा. वहीं काराकाट में भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया. पाटलिपुत्र में रामकृपाल यादव और आरा में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह की हार भी जातिगत ध्रुवीकरण के कारण ही हुई. लालू द्वारा मोदी का डर दिखाना भी कारगर नहीं हो सका.''

चुनाव में जेडीयू की स्ट्राइक रेट बेहतर

अब राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर बड़े भाई की भूमिका में दिखेंगे. हालांकि, उनकी पार्टी जेडीयू ने 12 सीट पर ही जीत दर्ज की है, लेकिन बीजेपी को भी इतनी ही सीटें मिली हैं. जेडीयू ने 14 और बीजेपी ने 17 उम्मीदवार उतारे थे. जेडीयू का स्ट्राइक रेट बीजेपी से बेहतर रहा. इनकी सहयोगी व चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने पांच जगहों पर चुनाव लड़ा था और सभी पर जीत दर्ज की. 2019 की तुलना करें, तो बीजेपी को पांच और जेडीयू को चार सीट का नुकसान हुआ है.

पत्रकार शिवानी सिंह कहती हैं, ''केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह व आरके सिंह को जिस तरह कड़ी टक्कर मिली है, उस पर बीजेपी को चिंतन करना चाहिए. आरके सिंह तो हार ही गए. साथ ही, यह भी देखने की जरूरत है कि बीजेपी को जेडीयू का वोट किस हद तक ट्रांसफर हो सका. अगर जमीन पर ऐसा वाकई हुआ होगा, तो उसे पांच सीटों का नुकसान नहीं होता.''

वैसे बिहार के चुनावी नतीजों में यह साफ दिख रहा कि अगर बीजेपी नीतीश कुमार को वापस अपने खेमे में नहीं लाती, तो उसे उत्तर प्रदेश की तरह ही खासा नुकसान संभव था. बीजेपी को अब नीतीश कुमार को मजबूती से अपने साथ जोड़े रखना पड़ेगा. इसमें कोई दोराय नहीं कि नीतीश केंद्र की सरकार के साथ-साथ आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी की मजबूरी बन चुके हैं. पर उनके अतीत को देखते हुए अटकलें एक बार फिर तेज हैं कि कहीं नीतीश फिर से न पलट जाएं.

एसटी सीटों पर भाजपा को करारी शिकस्त

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन को मिली हार, गीता कोड़ा भी रही फेल

सत्येन्द्र, रांची

झारखंड के आदिवासी बहुल सीटों पर बीजेपी को मिली करारी हार ने प्रदेश भाजपा के नेताओं को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है. बीजेपी के नेता आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अभी से ही इस हार की समीक्षा करने में जुट गये है. चुनाव परिणाम के मुताबिक अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व उन तीनों सीटों (खूंटी, दुमका और लोहरदगा) पर भाजपा कोई करिश्मा नहीं दिखा पाई. वैसे भाजपा ने एसटी के लिए रिजर्व पांच सीटों में से चार सीटों पर एक्सपेरिमेंट भी किया, जो फेल हो गया.

मोदी कैबिनेट में कद्दावर नेता बनकर उभरे अर्जुन मुंडा का निशाना भी इस चुनाव में चूक गया. केंद्र में जनजातीय मामलों के मंत्री पद पर रहते हुए अर्जुन मुंडा खूंटी सीट हार गये. उन्हें कांग्रेस के कालीचरण मुंडा ने शिकस्त दी. दरअसल, 2019 के चुनाव में भी अर्जुन मुंडा को कालीचरण से कड़ी टक्कर मिली थी लेकिन अंत में महज 14 सौ से कुछ ज्यादा वोट के अंतर से उन्हें जीत मिली थी. इसबार बाजी पलट गई. अब सवाल है कि अर्जुन मुंडा को इतनी बड़ी शिकस्त कैसे मिली. इसकी कई वजहें मानी जा रही हैं. एक तो मुस्लिम और ईसाई वोट का ध्रुवीकरण हुआ. दूसरा यह कि पथलगड़ी की वजह से पिछले चुनाव मं वोट बहिष्कार करने वालों ने इसबार खुलकर वोटिंग में भाग लिया. तीसरा कारण बना आदिवासी वोट बैंक में बिखराव.

सोरेन परिवार से अलग होकर दुमका से चुनाव लड़ी बहू सीता भी नहीं बचा पाईं सीट

भाजपा ने दुमका में अपने सीटिंग सांसद सुनील सोरेन का टिकट काटकर सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन को मैदान में उतारा था. सीता से भाजपा को काफी उम्मीदें थी. भाजपा मानकर चल रही थी कि सीता के आने से आदिवासी वोट बैंक पर असर पड़ेगा. क्योंकि शिबू सोरेन के साथ सीता सोरेन के दिवंगत पति दुर्गा सोरेन ने झामुमो को खड़ा करने में अहम भूमिका निभायी थी. यही वजह है कि सीता सोरेन लगातार जामा विधानसभा सीट से जीत रही थीं. लेकिन मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने और कल्पना सोरेन के एक्टिव होने से वह नाराज थी. आखिर में उन्होंने पारिवारिक विरासत वाली पार्टी को छोड़कर भाजपा के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया. उन्होंने चुनावी सभाओं पर अपने साथ हुए सौतेला व्यवहार का जिक्र भी किया. लेकिन झामुमो के शिकारीपाड़ा से सात बार के विधायक नलिन सोरेन से भी मुकाबला नहीं कर पाई. उनका जादू नहीं चला. बेशक, कुछ राउंड में सीता सोरेन को बढ़त मिली लेकिन राउंड दर राउंड उनकी बढ़त का फासला कम होता चला गया और वह चुनाव हार गयी.

लोहरदगा में भी भाजपा को लगा झटका

भाजपा को तीसरा बड़ा झटका लोहरदगा सीट पर लगा है. पार्टी ने सीटिंग सांसद सुदर्शन भगत का टिकट काटकर समीर उरांव को प्रत्याशी बनाया था. इस चुनाव से पहले वह राज्यसभा सांसद भी थे. यही नहीं वह वर्तमान में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं. इसके बावजूद उन्हें इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत से मात खानी पड़ी जबकि इस सीट को लेकर झामुमो और कांग्रेस में काफी तनातनी हुई थी. बिशुनपुर से झामुमो विधायक चमरा लिंडा के चुनाव में उतरने से झामुमो असहज महसूस कर रही थी. चमरा के नहीं मानने पर पार्टी ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की थी. लेकिन ऐसी चर्चा हो रही थी कि चमरा के मैदान में होने से भाजपा को फायदा होगा. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा.

राजमहल व सिंहभूम में जीत की उम्मीद पर फिरा पानी

इस बार के चुनाव में भाजपा के सभी नेताओं का दावा था कि वह ना सिर्फ अपने तीनों सीटिंग रिजर्व सीटों पर जीत हासिल करेगी बल्कि राजमहल और सिंहभूम में भी कमल खिलेगा. सिंहभूम में कांग्रेस की एकमात्र सांसद रहीं गीता कोड़ा को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया था. हो आदिवासी समाज से आने वाली गीता कोड़ा भी पूरे कांफिडेंस में थी. उनके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाईबासा में चुनावी सभा की थी. लेकिन कोल्हान की ज्यादातर विधानसभा सीटों पर झामुमो की जीत होने का फायदा झामुमो प्रत्याशी जोबा मांझी को मिला ओर बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा को हार का सामना करना पड़ा.

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का करिश्मा काम नही आया : झारखंड के राजनीतिक गलियारें में चर्चा चल रही है कि एसटी के लिए रिजर्व सभी तीन वीनिंग सीटों के अलावा शेष दो सीटों पर हार का ठिकरा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर फूट सकता है. क्योंकि पार्टी के शीर्ष नेताओं ने इनपर पूरा भरोसा जताया था. बाबूलाल मरांडी को खुली छूट मिली थी. टिकट बंटवारे में भी उनकी अहम भूमिका था. बाबूलाल मरांडी ऐसे नेता रहे हैं जो दुमका सीट पर शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रुपी सोरेन को हरा चुके हैं. लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के नाते वह कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए.

मतदाताओं ने ताला मरांडी के भाग्य पर भी जड़ दिया ताला

भाजपा का यही हाल राजमहल सीट पर भी हुआ। पार्टी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी पर दांव लगाया था। इस सीट पर बोरियो से झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम के ताल ठोकने की वजह से चुनाव के त्रिकोणीय बनने के आसार थे। लेकिन मुस्लिम और यादव वोट की गोलबंदी के साथ-साथ आदिवासी वोट में बिखराव ने ताला मरांडी के भाग्य पर ताला जड़ दिया।

हार के बाद अर्जुन मुंडा का राजनीतिक भविष्य?

लोकसभा चुनाव में झारखंड में बड़ा उलटफेर हुआ। भाजपा को अपनी तीन सीटें गंवानी पड़ी तो कांग्रेस-झामुमो पांच सीटों पर कब्जा जमाने में सफल रही। राज्य की कुल 14 सीटों में से पिछली बार भाजपा ने 11 और उसकी सहयोगी पार्टी आजसू ने गिरिडीह सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं झामुमो ने राजमहल और कांग्रेस ने चाईबासा सीट जीती थी। इस बार भाजपा को रांची, धनबाद, पलामू, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, जमशेदपुर और गोड्डा सीट पर सफलता मिली तो आजसू फिर गिरिडीह सीट बचाने में सफल रहा।

एनडीए और इंडिया के लिए प्रतिष्ठा बनी खूंटी और दुमका भी भाजपा ने गंवा दी। यहां से अर्जुन मुंडा और हाल ही में झामुमो छोड़कर भाजपा में शामिल हुई सीता सोरेन सीट नहीं बचा सकी। दो बार चुनाव जीतने वाली लोहरदगा संसदीय सीट भी भाजपा ने गंवा दी। पार्टी ने यहां से निवर्तमान सांसद सुदर्शन भगत को बदलकर समीर उरांव पर दांव खेला था।

खूंटी लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा एक लाख से अधिक वोट से हार गए। इस चुनाव में भाजपा ने खूंटी में पूरी ताकत झोंक दी थी। कई योजनाओं की शुरुआत खूंटी से की। पीएम खुद उलिहातू पहुंचे और भगवान बिरसा मुंडा की धरती को नमन किया। राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नेताओं ने प्रचार किया लेकिन इस प्रचार का लाभ पार्टी को नहीं मिला। जानिए, इस हार के बाद केंद्रीय मंत्री रहे अर्जुन मुंडा का राजनीतिक भविष्य क्या होगा ?

बाबूलाल मरांडी इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष के पद पर है। अर्जुन मुंडा अगर राज्य की राजनीति में लौटते हैं तो विधानसभा में भाजपा किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी इसे लेकर असमंजस की स्थिति हो सकती है। अर्जुन मुंडा, रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी इस तीन खेमें में बंटे पार्टी के कई नेता अपनी लॉबी तलाशेंगे।

अर्जुन मुंडा की वापसी के साथ ही भाजपा में गुटबाजी एक बार फिर तेज हो सकती है। बाबूलाल मरांडी अपने साथ जेवीएम के कई नेताओं को लेकर आये थे। प्रदेश भाजपा में यह चर्चा तेज रही है कि बाबूलाल अपने पुराने साथियों पर ज्यादा मेहरबान रहते हैं। अर्जुन मुंडा की राज्य में राजनीति में वापसी होती है तो ऐसा धड़ा जो बाबूलाल से नाराज है, अर्जुन मुंडा के साथ जा सकता है। केंद्र का रुख करने के बाद कई विधायक और भाजपा के नेता जो अर्जुन मुंडा के साथ थे, उनसे अलग होकर राज्य की राजनीति में अपना सुरक्षित ठिकाना तलाश रहे थे। अर्जुन मुंडा की वापसी से वह दोबारा एक्टिव हो सकते हैं।

बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष हैं। राज्य में भाजपा के प्रदर्शन की जिम्मेदारी उनकी भी है। ऐसे में भाजपा के प्रदर्शन में आई गिरावट का असर बाबूलाल पर भी पड़ेगा। भाजपा की जो सीटें घटी हैं, उसकी वजह पर पार्टी मंथन करेगी। बाबूलाल अपनी पार्टी को बूथ स्तर पर कितने मजबूत कर पाए इस पर भी सवाल होगा। क्या भाजपा को सिर्फ मोदी के चेहरे पर वोट मिला या स्थानीय नेताओं की भी मजबूती इतनी थी कि वो इसे वोट में बदला पाया, इसका भी आकलन होगा। इस आकलन से तय होगा पार्टी में कौन कितना मजबूत है। क्या बाबूलाल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मतदाताओं तक पार्टी का मुद्दा पहुंचाने में सफल रहे इसका भी आकलन होगा। ऐसे में पार्टी इस पर विचार कर सकती है कि भविष्य में भाजपा विधानसभा चुनाव में किस के चेहरे पर दांव खेलेगी।

अर्जुन मुंडा अगर राज्य की राजनीति में लौटते हैं तो हो सकते हैं कई बड़े बदलाव

अर्जुन मुंडा अगर राज्य की राजनीति में लौटते हैं तो भाजपा में स्थानीय स्तर पर संगठन में कई बड़े बदलाव की संभावना है। अर्जुन मुंडा भाजपा के पुराने और मजबूत नेता है। इस वक्त पार्टी की कमान बाबूलाल मरांडी के हाथ में है। अगर राज्य की राजनीति में अर्जुन मुंडा की वापसी होती है तो विधानसभा चुनाव में पार्टी के पास बाबूलाल के साथ एक पुराना चेहरा भी होगा हालांकि इस हार से अर्जुन मुंडा का कद जरूर घटा है लेकिन राज्य की राजनीति में स्थिति अलग हो सकती है। अर्जुन मुंडा झारखंड की राजनीति में बड़ा चेहरा माने जाते हैं। वह मुख्यमंत्री भी रहे हैं। राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री थे।

झारखंड में 30 कोल ब्लॉक का आवंटन, मात्र 07 में ही उत्पादन

खनिज बहुल राज्य झारखंड में भारत सरकार ने कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट (सीएमएसपी) तहत 30 कोल ब्लॉक आवंटित किए हैं. इसमें ज्यादातर निजी कंपनियां है. कुछ कोल ब्लॉक बोली लगाकर कोल इंडिया की कंपनियों को भी मिला है. इसमें से मात्र 7 कोल ब्लॉक पर ही खनन का कार्य शुरू हो पाया है. भारत सरकार ने कई कंपनियों को अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए कोल ब्लॉक आवंटन किया है. इसका उद्देश्य जल्द से जल्द कंपनियों को विकास में भागीदार बनना है. पहले बिजली उत्पादकों, स्टील कंपनी आदि कोल इंडिया के माध्यम से ही कोयले की आपूर्ति होती थी. अब इस तरह की कंपनियां कोल ब्लॉक लेकर अपनी जरूरत का कोयला निकाल सकती है. झारखंड में 10 वर्ष पहले आवंटन प्राप्त कई कंपनियों ने अब तक खनन कार्य शुरू नहीं किया है. इसमें कई कंपनियां ऐसी है जिनको नीलामी के पहले चरण में ही कोल ब्लॉक आवंटन हुआ है. भारत सरकार खनन नहीं करने वाली कंपनियों के स्टेटस का समय-समय पर समीक्षा करती है. इसमें खनन शुरू करने के लिए कहा जाता है. खनन शुरू नहीं करने पर भारत सरकार ने दंड का भी प्रावधान किया है.

मालूम हो कि चट्टी बरियातू कोल ब्लॉक एनटीपीसी को प्राप्त हुआ है. कठौतिया हिंडाल्को को मिला है. केरेडारी एनटीपीसी को, पंचुवाडा सेंट्रल पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को मिला है. पंचुवाड़ा नॉर्थ पश्चिम बंगाल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के हिस्से में गया है. तुवेद डीवीसी को मिला है और डुमरी हिंडाल्को को प्राप्त हुआ है. इन सभी कॉल ब्लॉक में खनन कार्य प्रारंभ है.

कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन का गोल्डन जुबली समारोह प्रारंभः कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन का बहुप्रतिक्षित गोल्डन जुबली समारोह यहां प्रारंभ हो गया है. संगठन का मुख्य समारोह इसी माह 25 जून को राजधानी रांची में आयोजित होगा. पिछले दिनों राजधानी के खेलगांव में संगठन के तत्वावधान में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि सीसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक निलेंदु कुमार सिंह ने कहा कि हम आने वाले वर्षों में केवल कोयला से ही ऊर्जा की जरूरत पूरी नहीं करेंगे बल्कि कोल से केमिकल, कोल से गैस, कोल ओबी से बालू, कोल ओबी से सेरामिक, नैनो कार्बन, सौर और विंड ऊर्जा भी तैयार करेंगे. हम देश में प्रदूषण कम करने के लिए सतत प्रयास करते रहेंगे इसके लिए तमाम लोगों के सहयोग की जरूरत होगी. आजादी के 100 वर्ष पूरे होने के समय देश 2047 में नवनिर्माण के अगले कदम पर खड़ा होगा.

सीसीएल के निदेशक कार्मिक एच एन मिश्रा ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों की जो भी परेशानी है उसे दूर करने में कंपनी कोई कसर नहीं छोड़ेगी.

सीवीओ पंकज कुमार ने कहा कि संगठन की एकता में ही ताकत होती है. कोल इंडिया केवल एक कंपनी नहीं यह सीधे राष्ट्र निर्माण से जुड़ी है.

सीएमओएआई अपेक्स के अध्यक्ष डीएन सिंह ने कहा कि अधिकारी विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं, जहां कोई सुविधा नहीं होती. वहां हम खनन करते हैं लेकिन कई मौके पर हमारी नहीं सुनी जाती है. नए अधिकारियों की वेतन विसंगति को दूर करने में परेशानी हो रही है. कोल इंडिया प्रबंधन का रुख हमारे पक्ष में है लेकिन रास्ता नहीं निकल रहा है. उम्मीद है कि चुनाव के बाद कुछ अच्छी खबर आए. मौके पर सीसीएल सीएमओएआई के सचिव केएल यादव ने भी अपने विचार रखें कोल इंडिया की सभी कंपनियों से आने वाले सीएमओएआई के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया.

एक लाख करोड़ रुपए की विकास योजनाओं को मंजूरीः अमरेंदु

सेल SAIL

भारत सरकार ने सेल की एक लाख करोड़ रुपए की विकास योजनाओं को मंजूरी दे दी है. वर्ष 2030 तक इस्पात उद्योग की क्षमता बढ़ाकर 35 मिलियन टन प्रतिवर्ष करने के लिए डिजाइन किया गया है. सेल ने पश्चिम बंगाल में अपने इस्को स्टील प्लांट के ग्रीन फील्ड विस्तार की योजना बनाई है. यह मिल तेल, गैस और ऑटोमेटिव क्षेत्र के लिए उच्च ग्रेड हॉट रोल्ड कोएल और एपी ग्रेड स्टील उत्पाद बनाएगी. सेल के अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश ने यहां यह बात कही. उन्होंने कहा कि यह परियोजना लगभग 4 वर्षों में पूरी होने की उम्मीद है. सेल बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी है, जबकि बोकारो स्टील प्लांट के विस्तार की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति के साथ सेल आगे बढ़ रहा है. कंपनी वित्त वर्ष 2030 31 के अंत तक कच्चे स्टील के प्रति टन कार्बन उत्सर्जन को 2.3 टन से कम करने के उद्देश्य से समयबद्ध कार्य योजनाएं तैयार कर रही है. श्री प्रकाश ने बताया कि दुर्गापुर स्टील प्लांट में ब्राउन ब्राउन फील्ड विस्तार और आधुनिकीकरण की योजनाएं शुरू की गई है. 1.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाली एक नई थर्मों मैकेनिक ट्रीटेड मिल विस्तार योजना का हिस्सा है.

एनटीपीसीः वृक्षारोपण के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया

एनटीपीसी कोयला खनन मुख्यालय/एनएमएल, रांची में केंद्रीय पेट्रोरसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी), रांची के नए परिसर में बड़े पैमाने पर फल देने वाले पौधों के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया.

स्वयंसिद्धा लेडीज क्लब के सहयोग से 5 जून, 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस पर सामूहिक वृक्षारोपण का आयोजन किया गया.

पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, स्वयंसिद्ध लेडीज क्लब की अध्यक्ष श्रीमती रेखा जैन ने फलदार पौधे लगाने की शुरुआत की, जिसके बाद श्रीमती शिखा रस्तोगी, उपाध्यक्ष, श्रीमती सुनीता पांडे, वरिष्ठ सदस्य, महासचिव, श्रीमती मनसा वर्मा, संयुक्त सचिव, दीपा कुमारी, कोषाध्यक्ष, श्रीमती स्निग्धा रानी मांझी और श्रीमती सपना पारीक और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे.

एनटीपीसी कोयला खनन परियोजनाओं ,पकरी बरवाडीह, चट्टीबरियातु, केरनदारी, बादाम, बनारडीह, दुलंगा और तलाईपल्ली कोयला खनन परियोजनाओं की से बड़ी संख्या में छात्रों सह परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया गया.

ये छात्र वर्तमान में सिपेट में प्लास्टिक प्रसंस्करण पाठ्यक्रमों पर कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जो की एनटीपीसी द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रायोजित है.

सीसीएल में मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 1 जून से 5 जून तक सीसीएल परिवार ने पर्यावरण जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया. 1 जून 2024 को निदेशक तकनीकी (योजना एवं परियोजना) श्री सतीश झा ने उद्घाटन कर विभिन्न प्रतियोगिताओं का शुभ आरंभ किया जिनमें लगभग 200 बच्चों ने भाग लिया. पेंटिंग, क्विज, स्लोगन, निबंध एवं कविता पाठ का आयोजन किया गया. 3 जून 2024 को कर्मचारियों के लिए क्विज प्रतियोगिता का आयोजित हुई. 4 जून 2024 को सूती कपड़े का थैला एवं फलदार वृक्ष के पोधों का वितरण किया गया.

5 जून को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, श्री निलेन्दु कुमार सिंह की अध्यक्षता में ध्वजारोहण एवं शपथ ग्रहण किया गया.

05 जून को सीसीएल मुख्यालय, दरभंगा हाउस, रांची में आयोजित कार्यक्रम में सीसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, श्री निलेन्दु कुमार सिंह, निदेशक (वित्त), श्री पवन कुमार मिश्रा, निदेशक (कार्मिक), श्री हर्ष नाथ मिश्र, निदेशक तकनीकी (संचालन), श्री हरीश दुहान, निदेशक तकनीकी (योजना एवं परियोजना) श्री सतीश झा, सीवीओ, श्री पंकज कुमार, विभागाध्यक्ष (पर्यावरण) श्री राज कुमार सहित विभिन्न विभागों के महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष एवं बड़ी संख्या में सीसीएल कर्मी उपस्थित थे. इस अवसर पर कर्मियों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए शपथ लिया. इसके उपरांत निदेशकगण एवं सीवीओ ने पौधारोपण कर सभी को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया.

पर्यावरण दिवस के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत कर उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया. ज्ञातव्य हो कि कमांड क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पौधा एवं जूट बैग का वितरण किया गया. मंच संचालन मुख्य प्रबंधक (पर्यावरण), सुश्री संगीता ने किया.

कोल इंडिया ने भेल के साथ मिलकर नई अनुषंगी इकाई का गठन किया

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने कोयला से रसायन कारोबार चलाने के लिए एक अनुषंगी इकाई भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (बीसीजीसीएल) के गठन की घोषणा की है. सीआईएल ने बीएसई को दी सूचना में कहा कि नई इकाई में उसकी बहुलांश 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है जबकि शेष 49 प्रतिशत हिस्सेदारी बीएचईएल के पास है.

कोल इंडिया ने कोयला-से-रसायन व्यवसाय शुरू करने के लिए फरवरी में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे.

दोनों कंपनियों के इस संयुक्त उद्यम के गठन के लिए नीति आयोग और निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) की मंजूरी मिल गई है.

इसमें कहा गया है, "भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड का गठन कोयला-से-रसायन कारोबार के लिए मध्यवर्ती उत्पादों के रूप में अमोनिया एवं नाइट्रिक एसिड और अंतिम उत्पाद के रूप में अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करने के लिए किया गया है." इस बीच, कोल इंडिया लिमिटेड ने बर्दवान जिले में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (इसीएल) के सोनपुर बाजारी क्षेत्र में 13,052 करोड़ रुपये की कोयला-से-सिंथेटिक प्राकृतिक गैस परियोजना लगाने के लिए गेल के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं.

एसईसीएल के नए सीएमडी की खोज शुरू

सीएमडी प्रेम सागर मिश्रा का कार्यकाल 31 जनवरी 2025 तक, 01 फरवरी 2025 को पद रिक्त होगा

कोल इंडिया की दूसरी बड़ी अनुषांगिक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के नए सीएमडी की तलाश शुरू हो गई है.

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) ने एसईसीएल के सीएमडी पद के लिए वैकेंसी निकाली है. आवेदन करने की तिथि 12 जून, 2024 तक निर्धारित थी.

एसईसीएल के वर्तमान सीएमडी डा. प्रेम सागर मिश्रा का कार्यकाल 31 जनवरी, 2025 तक का है. एक फरवरी, 2025 को पद रिक्त होगा. पीएसईबी द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से सीएमडी का चयन किया जाएगा.

पेलमा कोयला खदान तभी शुरू होगी, जब पूरी होगी गांवों की मांग

एसईसीएल को आवंटित पेलमा कोयला खदान को शुरू करवा पाना टेढ़ी खीर है. अब पांच पंचायतों के सरपंचों ने एकजुट होकर एसईसीएल के सामने मांगें रखी हैं. इसमें 60 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजे के साथ नौकरी की भी मांग रखी गई है. कोल मिनिस्ट्री ने तमनार का पेलमा कोल ब्लॉक एसईसीएल को आवंटित किया है. इस कोल ब्लॉक का एमडीओ अडाणी ग्रुप को मिला है. आवंटन के बाद से ही ग्रामीणों के विरोध की वजह से सर्वे तक नहीं हो पा रहा है. अब पांच पंचायतों की ओर से मांग पत्र सामने आया है. ग्राम पंचायत पेलमा, उरबा, मिलूपारा, लालपुर और हिंझर के सरपंचों ने संयुक्त रूप से मांगें एसईसीएल के समक्ष रखी हैं.

उनकी प्रमुख मांग है कि सभी किसानों की पूरी जमीन ली जाए, किसी की एक डिसमिल जमीन भी न छोड़ी जाए. आठ गांवों में 60 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से या अधिकतम सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजा दिया जाए. प्रति एकड़ एक नौकरी भी दी जाए. नौकरी के एवज में मुआवजा 10 लाख रुपए दिया जाए. विस्थापन लाभ प्रति परिवार कम से कम 10 लाख रुपए दिया जाए.जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक के बाद नौकरी के लिए दस्तावेज जमा करने के छह महीने के अंदर नौकरी मिल जानी चाहिए. भूमिहीन परिवार को भी एमडीओ में नौकरी या दुकान की वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए.

2005 से पहले से काबिज वन भूमि एवं सरकारी भूमि धारक को पट्टा प्रदान कर मुआवजा व अन्य लाभ दिया जाए. सरपंचों का कहना है कि भूमि व परिसंपत्तियों का मुआवजा एकमुश्त दिया जाए. गांव को एक साथ खाली करने पर प्रति परिवार 10 लाख रुपए पारितोष राशि दी जाए. विस्थापन स्थल ग्रामीणों की सहमति से चुनी जाए. जिस तिथि को सर्वे होगा, उसे ही कट ऑफ डेट माना जाए. ग्रामीणों ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भी नौकरी का अनुमोदन दिया जाए जो 18 वर्ष होने के बाद दी जाए. खाता विभाजन पर लगाई गई रोक हटाने की मांग भी की जाए.

ऐसे तो शुरू नहीं हो सकेगी खदान : पांचों सरपंचों ने जिस तरह की मांगें एसईसीएल के समक्ष रखी हैं, वह सरकारी गाइडलाइन के अनुसार पूरी होनी संभव नहीं है. मुआवजा दर किसी भी गांव में 60 लाख रुपए प्रति एकड़ नहीं है. इन मांगों से प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी. फिलहाल एसईसीएल और ग्रामीणों के बीच गतिरोध जारी रहेगा.

गेवरा, कुसमुंडा, कोरबा एवं चिरमिरी क्षेत्र में विजिलेंस टीम ने दी दस्तक

एसईसीएल सतर्कता विभाग की टीम द्वारा गेवरा, कुसमुंडा, कोरबा एवं चिरमिरी क्षेत्रों का दौरा किया गया. सीवीओ श्री जयंत कुमार खमारी के मार्गदर्शन में क्षेत्रीय दौरे पर गयी इस टीम द्वारा गेवरा, कुसमुंडा एवं कोरबा क्षेत्र की मानिकपुर एवं चिरमिरी ओसी खदान में आगामी मानसून को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की गई.

कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार टीम द्वारा मानसून की शुरुआत से पहले ही सड़कों और प्रेषण बिंदुओं के खराब रखरखाव के कारण प्रेषण में किसी भी समस्या की संभावना से बचने के लिए हॉल रोड और कोयला परिवहन सड़कों की स्थिति का निरीक्षण किया गया. साथ ही सड़कों की वर्तमान गुणवत्ता की जांच हेतु सैंपल भी लिया गया.

टीम ने हॉल रोड/कोयला परिवहन सड़क और प्रेषण बिंदुओं के रखरखाव से संबंधित चल रहे सभी अनुबंधों की भी जांच की एवं वर्तमान में चल रहे कार्यों का भी निरीक्षण किया. सतर्कता विभाग की टीम की इस पहल से आगामी मानसून की तैयारियों में पारदर्शिता एवं बेहतर कार्यान्वयन में मदद मिल रही है जिससे मानसून के दौरान भी खदान का सुचारु रूप से संचालन एवं कोयले का प्रेषण सुनिश्चित हो सकेगा.

बिहार की धरती उगलेगी सोना, करोड़ों टन सोने का अनुमान, जल्द होगी खुदाई

किसी जमाने में भारत को सोने की चिड़िया नाम से जाना जाता था. लेकिन सोने के मामले में बिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है. जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक, बिहार के जमुई जिले में करमाटिया, झाझा और सोने जैसे इलाकों में करोड़ों टन सोने की खदानों के बारे में पता चला है. यह सोना देश के कुल गोल्ड रिजर्व का लगभग 44 फीसदी है

बिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है. अब वह दिन दूर नहीं जब बिहार की धरती सोना उगलेगी. बिहार के जमुई जिले में सबसे बड़ा सोने के भंडार के बारे में पता चला है. जमुई जिले में करमाटिया, झाझा और सोनो जैसे इलाकों में करोड़ों टन सोना छिपा हो सकता है. जियोलॉजिकल सर्वे में इस बात की जानकारी सामने आई है. फिलहाल बिहार में बहुत सा सोना दबा हुआ है, जिसे बस निकालने भर की देरी है. अगर यह सोना निकला तो बिहार में बहार आ जाएगी. गोल्ड रिजर्व के मामले में बिहार देश में पहले पायदान पर है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जमुई जिला में 37.6 टन खनिज युक्त अयस्क समेत 22.28 करोड़ टन सोने का भंडार मौजूद है. यह देश के कुल गोल्ड रिजर्व का लगभग 44 फीसदी है. जानकारी यह भी मिली है कि राज्य खनन और भूविज्ञान विभाग द्वारा जमुई में सोने के भंडार की खोज के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अलावा सर्वे में लगी अन्य एजेंसियों से भी सलाह मशविरा लिया जा रहा है. वहीं जमुई के पड़ोसी जिले बांका के कटोरिया इलाके में भी सोने की खदान के बारे में पता चला है. इसके लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम सर्वे की काम में जुटी हुई है.

पिछले साल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में कहा था कि बिहार के पास भारत के सोने के भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा है. इस मामले में लिखित तौर पर उत्तर में कहा गया था कि बिहार में 222.885 मिलियन टन स्वर्ण धातु है. पुराने तकनीक से जमीन के अंदर से खुदाई कर सोना निकालने में अधिक खर्च होने के कारण इसकी खुदाई रोक दी गई है. केंद्र सरकार ने सोना समेत अन्य धातुओं की खुदाई से संबंधित नियमों में बदलाव कर दिया है. इसमें सोना समेत अन्य धातुओं के लिए जी 4 स्तर का लाइसेंस देने के लिए नीलामी होगी. जिससे खनिज की खोज और खनन के क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक के अलावा निजी सेक्टर की भागीदारी के आसार हैं. जिससे सोना को निकालने में लगने वाली खर्च कम होने की उम्मीद जताई जा रही है.

सेल के दिव्यांग अधिकारियों-कर्मचारियों को स्पेशल सीएलएल का तोहफा

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल के दिव्यांग कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है. सेल प्रबंधन ने 4 सीएलएल का तोहफा दे दिया है. लंबे संघर्ष के बाद यह अधिकार कार्मिकों को दे दिया गया है. डीपीई गाइडलाइन पर अमल कराने की मांग लंबे समय से की जा रही थी.

स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया-सेफी के चेयरमैन व बीएसपी आफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर ने बड़ा दावा किया है. सेल चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश और डायरेक्टर पर्सनल केके सिंह का धन्यवाद अदा किया है. एके बंछोर ने बताया कि पूर्व चेयरमैन सोमा मंडल के कार्यकाल में पहला ज्ञापन 18 अप्रैल 2022 को सेफी ने प्रबंधन को सौंपा था.

इसके बाद सेफी कोर कमेटी और सेल प्रबंधन की हर मीटिंग में यह मुद्दा उठाता रहा है. जनवरी की मीटिंग में चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश और डायरेक्टर पर्सनल केके सिंह ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही यह मुद्दा हल कर दिया जाएगा. इसका साक्ष्य भी कार्मिकों को मिल चुका है. वहीं, परिवहन भत्ते को बेसिक पर 5 प्रतिशत बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन, अपेक्षाकृत बढ़ोत्तरी नहीं हो सकी है.

कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन का गोल्डन जुबली समारोह प्रारंभ

कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन का बहुप्रतिक्षित गोल्डन जुबली समारोह यहां प्रारंभ हो गया है। संगठन का मुख्य समारोह इसी माह 25 जून को राजधानी रांची में आयोजित होगा। पिछले दिनों राजधानी के खेलगांव में संगठन के तत्वावधान में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि सीसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक निलेंदु कुमार सिंह ने कहा कि हम आने वाले वर्षों में केवल कोयला से ही ऊर्जा की जरूरत पूरी नहीं करेंगे बल्कि कोल से केमिकल, कोल से गैस, कोल ओबी से बालू, कोल ओबी से सेरामिक, नैनो कार्बन, सौर और विंड ऊर्जा भी तैयार करेंगे। हम देश में प्रदूषण कम करने के लिए सतत प्रयास करते रहेंगे इसके लिए तमाम लोगों के सहयोग की जरूरत होगी। आजादी के 100 वर्ष पूरे होने के समय देश 2047 में नवनिर्माण के अगले कदम पर खड़ा होगा।

सीसीएल के निदेशक कार्मिक एच एन मिश्रा ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों की जो भी परेशानी है उसे दूर करने में कंपनी कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

सीवीओ पंकज कुमार ने कहा कि संगठन की एकता में ही ताकत होती है। कोल इंडिया केवल एक कंपनी नहीं यह सीधे राष्ट्र निर्माण से जुड़ी है।

सीएमओएआई अपेक्स के अध्यक्ष डीएन सिंह ने कहा कि अधिकारी विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं, जहां कोई सुविधा नहीं होती। वहां हम खनन करते हैं लेकिन कई मौके पर हमारी नहीं सुनी जाती है। नए अधिकारियों की वेतन विसंगति को दूर करने में परेशानी हो रही है। कोल इंडिया प्रबंधन का रुख हमारे पक्ष में है लेकिन रास्ता नहीं निकल रहा है। उम्मीद है कि चुनाव के बाद कुछ अच्छी खबर आए। मौके पर सीसीएल सीएमओएआई के सचिव केएल यादव ने भी अपने विचार रखें कोल इंडिया की सभी कंपनियों से आने वाले सीएमओएआई के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया।

नाल्को का तीसरी तिमाही का शुद्ध लाभ 137% बढ़कर 488 करोड़ हुआ

खान मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का 'नवरत्न' उद्यम तथा देश के अग्रणी एल्यूमिना और एल्यूमीनियम निर्माता और निर्यातक ने दिसंबर 2023 को समाप्त तीसरी तिमाही में 488 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है।

कल भुवनेश्वर में आयोजित बैठक में बोर्ड द्वारा रिकॉर्ड किए गएवित्त वर्ष 24 की तीसरी तिमाही के समीक्षा किए गए वित्तीय परिणामों के अनुसार, नालको ने चालू वित्त वर्ष की पिछली तिमाही के 206 करोड़ रुपये की तुलना में 137% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है। दिसंबर 2023 को समाप्त नौ महीनों के लिए शुद्ध लाभ 1044 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 1023 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 24 की तीसरी तिमाही में कुल आय वित्त वर्ष 23 की तीसरी तिमाही के3358 करोड़ रुपये की तुलना में 3398 करोड़ रुपये रही।

उत्पादन के मोर्चे पर, नालको ने 3,45,086 मीट्रिक टन के उच्चतम संचयी धातु उत्पादन के साथ मजबूत वृद्धि हासिल की है। इसी तरह, बिक्री के मोर्चे पर, कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों के दौरान 3,49,419 मीट्रिक टन की अब तक की सबसे अधिक संचयी धातु बिक्री भी हासिल की है।

नालको ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2 रुपये प्रति शेयर की दर से दूसरे अंतरिम लाभांश की भी घोषणा की है।

टी-20 विश्व कप क्रिकेट में भारत सबसे बड़ा दावेदार

करोड़ों का सवाल क्या सपना होगा साकार

भारत पूरे फॉर्म में, आयरलैंड पर जीत से मिशन वर्ल्ड कप की शुरुआत जबकि पहले ही मैच में अमेरिका के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त और उधर ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत भी जीत से

चंचल भट्टाचार्य

टी-20 विश्व कप क्रिकेट एक ऐसा मौका होता है जब न केवल भारत बल्कि दुनिया के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की आकांक्षा यही होती है कि उनका देश क्रिकेट का शहंशाह बने. विशेष रूप से भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाये तो यहाँ क्रिकेट खेल नहीं बल्कि एक ऐसा धर्म है जिसके प्रति अधिकांश खेल प्रेमियों के साथ ही आम लोगों का ज़बरदस्त समर्पण है. इसकी चाहत, जोश, जुनून, जज़्बा और समर्पण-समर्थन गज़ब का है.

इस बार टी-20 विश्व कप क्रिकेट का आयोजन अमेरिका में किया गया है और उसमें दुनिया के 20 देश अपनी किस्मत के साथ-साथ अपनी काबिलियत, क्षमता और टीम भावना को भी आजमायेंगे साथ ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम उसे ही मिलेगा जो अव्वल होगा. इसमें तीन देश ऐसे हैं जो पहली बार विश्व कप क्रिकेट में भाग लेंगे. कनाडा, युगांडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, तीन देश ऐसे हैं जो पहली बार विश्व कप क्रिकेट में भाग लेंगे जबकि पापुआ न्यूगिनी एकमात्र ऐसा देश है जिसने 2021 के विश्व कप में अपना तीन मैच खेला था और तीनों ही हार गये थे. इसके अलावा इस विश्व कप क्रिकेट में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, आयरलैंड, नामीबिया, नेपाल, नीदरलैंड, न्यूज़ीलैंड, ओमान, पाकिस्तान, स्कॉटलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और वेस्टइंडीज के साथ अपना भारत भी है.

अब तक के सभी टी-20 विश्व कप क्रिकेट मुक़ाबलों में खेले गये मैचों के मुकाबले और सभी के प्रदर्शन-परिणाम की बात की जाये तो भारत वही देश है जो 2007 में पहली बार आयोजित टी-20 विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन बन चुका है. भारत ने विश्व कप के अबतक के 8 मुक़ाबलों में 44 मैच खेले हैं जिसमें से 27 में जीत हासिल की है. भारत का स्कोर 63.95 प्रतिशत है जो अपेक्षाकृत काफी बेहतर है. इस बार 2024 में भी भारत को टी-20 विश्व कप क्रिकेट का दावेदार माना जा रहा है. भारत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड की भी चैंपियन की दावेदारी है.

भारत के लिये यह बेहद महत्वपूर्ण मौका है जब वह चैंपियन बनने का अपने बरसों-बरस के सपने को पूरा करें और खिताबी सूखा समाप्त हो. पिछले वनडे विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारने वाली भारतीय टीम भले

ही 2013 के बाद कोई भी आईसीसी खिताब जीतने में नाकाम रही हो लेकिन अबकी बार सभी दावेदारों में वह सबसे आगे है क्योंकि भारत की बल्लेबाजी, क्षेत्ररक्षण, गेंदबाजी और कप्तानी का जैसा सामंजस्य है वह आज किसी भी टीम के लिए आदर्श हो सकता है साथ ही विरोधियों के लिये सिर दर्द का कारण क्योंकि किसी को भी परास्त करने के लिये वह काफी है. वर्तमान में दुनिया के नंबर एक टी-20 टीम भी भारत ही है जिसका कप्तान रोहित शर्मा के नेतृत्व में विनिंग परसेंटेज (जीत का आँकड़ा) शानदार रहा है. इसके अलावा भारत के पास विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव जैसे अनेक धुरंधर बल्लेबाज हैं तो बुमराह जैसे तेज गेंदबाज भी हैं. सभी अपने पूरे फॉर्म में चल रहे हैं. भारत के स्पिन गेंदबाजों का सामना करना भी विपक्षी टीम के लिये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा. पिछले टी-20 वर्ल्ड कप के बाद से भारत ने अबतक खेले गये अपने 28 मैच में से 18 में जीत हासिल की है. भारत, दुनिया में टी-20 क्रिकेट के मामले में दुनिया की नंबर एक टीम है जिसे अमेरिका और वेस्टइंडीज में खेलने का अनुभव भी है जो अभी अमेरिका में आयोजित हो रहे हैं इस वर्ल्ड कप क्रिकेट में बहुत काम आयेगा.

रोहित शर्मा की कप्तानी में पिछली बार भारतीय टीम सेमीफाइनल तक पहुँची थी और इनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने अपने खेले गये 54 मैच में से 41 में जीत दर्ज की. विश्व चैंपियन की दावेदारी का एक और कारण यह भी है कि 15 सदस्यीय भारतीय दल में 13 खिलाड़ियों को 20 से ज्यादा टी-20 मैच खेलने का अनुभव है जबकि इनमें से 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जो इससे पहले भी टी-20 विश्व कप में खेल चुके हैं.

पहली नजर में अगर देखा जाये तो भारतीय खिलाड़ियों के पास क्षमता भरपूर है. बल्लेबाजी, गेंदबाजी, क्षेत्ररक्षण के साथ ही कप्तानी भी लाजवाब है. टीम के खिलाड़ियों के मध्य सामंजस्य भी पूरा है. लेकिन अभी विरोधी पर ध्यान देने की बजाय अपनी क्षमता से खेलने की जरूरत है. वास्तव में, सही और सटीक रणनीति सबसे ज्यादा जरूरी है जिसे अपने प्रत्येक मैच में विरोधियों की की रणनीति और उनकी क्षमता के अनुसार बदलना बहुत ज्यादा जरूरी होगा. यदि भारत ऐसा कर सके तो यह कोई बहुत मुश्किल नहीं कि भारत 2024 के टी-20 विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन बने.

पिछली बार भारत ने आईसीसी टूर्नामेंट 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी के रूप में जीत दर्ज की थी. ठीक उसके 2 साल पहले युवराज सिंह के शानदार प्रदर्शन के बलबूते भारत, विश्व कप क्रिकेट भी जीता था और उससे पहले 2007 में पहला टी-20 विश्व कप भी जीता था. 2007, 2011 और 2013 में मिली जीत की पृष्ठभूमि में महेंद्र सिंह धोनी की महत्वपूर्ण भूमिका थी. लेकिन अबकी बार भारतीय टीम में अपना करिश्माई खेल और कप्तानी का जौहर दिखाकर विरोधी को परास्त करनेवाले धोनी टीम का हिस्सा नहीं हैं और भारतीय टीम को उनकी कमी खलेगी. 2 जून को शुरू हुए वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में अमेरिका ने कनाडा को हराने के साथ ही इस क्रिकेट महाकुंभ की शुरुआत तो हो चुकी है लेकिन वाकई में

यदि एशियाई परिप्रेक्ष्य में बात की जाये तो अगले 9 जून से असली मुकाबला शुरू होगा जब भारत और पाकिस्तान की टीम आमने-सामने होगी. भारतीय और पाकिस्तान टीम में ही क्रमशः विराट कोहली और बाबर के रूप में दो ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जिन्हें विश्व कप टी-20 क्रिकेट में 4000 रन बनाने का शानदार अनुभव है. भारतीय टीम वैसे सितारों से भरी है जिसके कारण भारतीय टीम को दुनिया की नंबर एक टीम के साथ-साथ टी-20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े दावेदार के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है. टीम में एक-से-बढ़कर-एक स्टार खिलाड़ी हैं जो किसी भी मैच का परिणाम पलटने की क्षमता रखते हैं. टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव के साथ-साथ यशस्वी भी नजर आयेंगे जबकि मिडिल ऑर्डर में सैमसन एवं ऋषभ पंत और ये सभी जबरदस्त फॉर्म में हैं. जडेजा, अक्षर, हार्दिक, शिवम आदि भी वैसे ऑलराउंडर हैं जो अपनी करिश्माई बल्लेबाजी दिखाकर परिणाम पलट सकते हैं. बल्लेबाजी की अहम कड़ी बुमराह होंगे जिन्होंने वर्ल्ड कप क्रिकेट के साथ ही हाल के आईपीएल में जानदार परफॉर्मेंस किया है. इसके अलावा सिराज और अर्शदीप के साथ ही कुलदीप और चहल की मौजूदगी भी है जो भारतीय टीम के आधार हैं.

भारतीय परिप्रेक्ष्य में न्यूयॉर्क में आयोजित टी-20 वर्ल्ड कप के मामले में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि राहुल द्रविड़ का भारतीय टीम के कोच के रूप में यह अंतिम टूर्नामेंट होगा और संभावना व्यक्त की जा रही है कि द्रविड़ अब कोच के रूप में भारतीय टीम का हिस्सा बनने के लिये इच्छुक भी नहीं हैं.

2 जून को खेले गये एक अभ्यास मैच में भारत में बांग्लादेश को 60 रन से हरा दिया. वैसे तो यह अभ्यास मैच था लेकिन भारतीय दृष्टिकोण से यह जीत इसलिये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से हार्दिक पांड्या अपने फार्म में लौट आये हैं जबकि दिसम्बर 2022 में हुई एक गंभीर दुर्घटना में घायल होने के बाद भारतीय टीम में वापसी करते हुए ऋषभ पंत ने 32 गेंद की अपनी पारी में चार चौके और चार छक्कों की मदद से धुआंधार 53 रन बनाये. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 182 रन बनाये. उसके बाद बांग्लादेश की टीम 9 विकेट पर 122 बनाकर आउट हो गयी.

औपचारिक रूप से भारत का पहला मुकाबला 6 जून को आयरलैंड के साथ था और अबतक के टी-20 मुकाबले में आयरलैंड की टीम भारत से एक भी मुकाबला नहीं जीत सकी है. 2024 के विश्व कप में, भारत और आयरलैंड के बीच यह T20 का आठवां मुकाबला था और भारतीय टीम इसके लिये पूरी तरीके से तैयार थी. खूबसूरत बात यह भी थी कि आयरलैंड के खिलाफ में कप्तान रोहित शर्मा हमेशा मुखर होकर खेलते रहे हैं और अपने चौतरफा तेज आक्रमण के बलबूते भारत ने आयरलैंड को 8 विकेट से हरा दिया. रोहित शर्मा ने 37 गेंद में 52 रन बनाये. पहले गेंदबाजी करते हुए भारत ने आयरलैंड को 16 ओवर में 96 रन पर समेट दिया. हर्षदीप सिंह ने चार ओवर में 35 रन देकर दो विकेट लिये जबकि हार्दिक पांड्या ने 27 रन देकर तीन विकेट चटकाये. जसप्रीत बुमराह ने तीन ओवर में छह रन देकर दो विकेट और मोहम्मद सिराज ने तीन ओवर में 13 रन देकर एक विकेट लिया. भारत के तेज आक्रमण आक्रमण के सामने आयरलैंड के बल्लेबाज टिक नहीं सके और भारत को जीतने के लिए 97 रन की जरूरत थी जो उसने 12.2 ओवर में प्राप्त कर लिया. भारतीय टीम की ओर से रोहित के 52 के अलावा ऋषभ पंत ने 36 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया.

उधर शिकस्त के साथ पाकिस्तान की शुरुआत हो चुकी है. 6 जून को एक मुक़ाबले में 7 प्रवासी भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों से सुसज्जित अमेरिका की टीम ने सुपर ओवर में पराजित किया. सुपर ओवर में अमेरिका ने पहले बल्लेबाजी की और एक विकेट के नुकसान पर 18 रन बनाये जिसके जवाब में पाक खिलाड़ियों ने एक विकेट गँवा कर 13 रन ही बनाया. उधर एक अन्य मुक़ाबले में ऑस्ट्रेलिया ने ओमान को 39 रन से मात दी.

कुल मिलाकर एक बात निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत ने जबरदस्त शुरुआत की है और हमें यह आशा करनी चाहिये कि अंजाम भी बेहतर ही होगा. अर्थात भारत अबकी बार 2024 में फिर से टी-20 विश्व कप क्रिकेट का वैसा शहंशाह होगा जिसकी अद्भुत खुशी देश के लोगों को होगी.

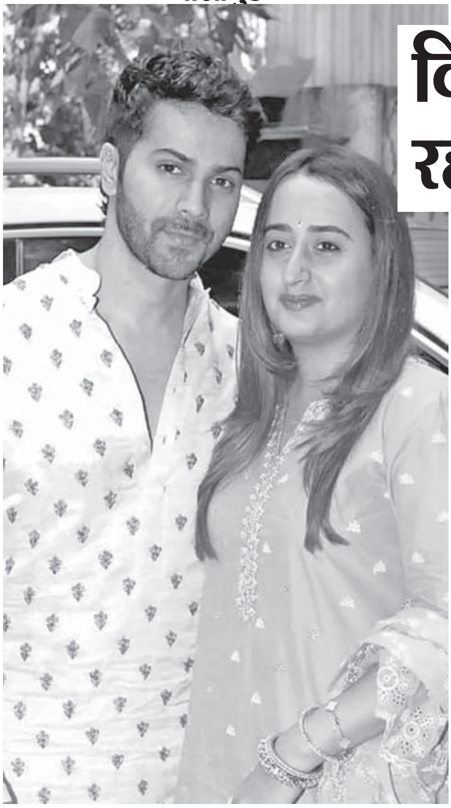

किराए के मकान में रहेंगे अब वरुण

वरुण धवन और नताशा दलाल हाल ही में माता-पिता बने हैं। उनके घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया है। हाल ही में वरुण और नताशा को अस्पताल के बाहर देखा गया था, जब एक्टर ने अपने हाथ में बिटिया को लिया हुआ था। अब इसी बीच वरुण और नताशा को लेकर खबर आ रही है कि वो अपना खुद का घर छोड़ दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं। हालांकि इस खबर से थोड़ी हैरानी होना तो लाजमी है क्योंकि हर किसी के दिमाग में ये प्रश्न तो उठेगा ही कि बेटी के जन्म के तुरंत बाद ही वो किराए के घर में क्यों जा रहे हैं.

ऋतिक का घर लिया किराए पर : वरुण धवन और नताशा दलाल जल्द ही अपने नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। खबरों के अनुसार वो ऋतिक रोशन के घर में रहेंगे, हालांकि अभी उसमें खुद ऋतिक रह रहे हैं लेकिन जल्द ही वो दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। हालांकि अभी तक खुद एक्टर ने इस बात को ऑफिशियल नहीं किया है।

23 जून को शादी करेंगी सोनाक्षी सिन्हा

सोनाक्षी सिन्हा 23 जून को मुंबई में बॉलीवुड एक्टर जहीर इकबाल से शादी करने जा रही हैं. इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस शादी में कपल के फैमिली मेंबर्स और क्लोज फ्रेंड्स ही शामिल होंगे. इसके अलावा सोनाक्षी की हालिया रिलीज वेब सीरीज 'हीरामंडी' की स्टारकास्ट भी इस शादी पर इनवाइट की जाएगी. हालांकि, इस खबर पर अब तक दोनों की तरफ से कोई कन्फर्मेशन नहीं मिला है.

हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है. हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जहां पूरे सोशल मीडिया पर दबंग गर्ल और नोटबुक हीरो की शादी की खबरें जंगल में आग की तरह फैली हुई हैं वहीं अभी तक न तो इस कपल ने और न ही उनके परिवार वालों ने कोई रिएक्शन दिया है.

फ्लैट में मिली काजोल की को-एक्ट्रेस नूर की सड़ी-गली लाश

द ट्रायल फेमस एक्ट्रेस नूर मालाबिका दास का 37 साल की उम्र में निधन हो गया है। इस खबर के सामने आते ही इंडस्ट्री में हलचल मच गई है। खबरों के अनुसार एक्ट्रेस की 6 जून को लोखंडवाला स्थित उनके घर से सड़ी गली हालत में लाश मिली है। देखने से तो लग रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है लेकिन अभी तक सही कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ऐसे में रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि ये हत्या है या आत्म हत्या।

पूर्व एयर होस्टेस और एक्ट्रेस नूर मालाबिका दास की लाश उनके अपार्टमेंट में सड़ी गली हालत में मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्ट्रेस ने पंखे से लटककर सुसाइड किया है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। नूर ने पिछले साल रिलीज हुई काजोल स्टारर वेबसीरीज 'द ट्रायल' में काम किया था।

नूर की मौत की खबर तब सामने आई जब पड़ोसियों ने फ्लैट से बदबू आने की शिकायत की। इसके बाद बीते 6 जून को ओशिवारा पुलिस ने लोखंडवाला स्थित उनके फ्लैट पर पहुंचकर देखा तो नूर का शव पंखे से लटका हुआ था। पुलिस ने तत्काल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

राशिफल

मेष

मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई माह की शुरुआत से लेकर दूसरे सप्ताह तक का समय अत्यंत ही शुभ है। इस दौरान करिअर और कारोबार से जुड़ी कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। लंबे समय से रोजी-रोजगार की तलाश में भटक रहे लोगों को मनचाहा अवसर प्राप्त हो सकता है। यह समय परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों के लिए भी शुभ साबित होगा।

वृषभ

वृष राशि के जातकों की जुलाई महीने की शुरुआत घर-पारिवार से जुड़ी जिम्मेदारियों और अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों को करते हुए बीतेगी। किसी इष्टमित्र या प्रभावी व्यक्ति की मदद से लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं। इस दौरान आपका पूरा फोकस परिवार की जरूरतों को पूरा करने और संबंधों को सुधारने में रहेगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए भी यह समय शुभता और सफलता लिए रहने वाला है।

मिथुन

मिथुन राशि के जातकों को जुलाई के महीने में समय,संबंध और धन का बहुत ज्यादा प्रबंधन करने की जरूरत रहेगी। यदि आप ऐसा करने में कामयाब रहे तो आपको माह की शुरुआत में ही व्यवसाय में मनचाहा लाभ होगा। पूर्व में किसी योजना में किए गए निवेश से मनाचाहा लाभ होगा। नौकरीपेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे।

कर्क

कर्क राशि के जातकों को जुलाई महीने के पूर्वार्ध में धन और सेहत दोनों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। माह की शुरुआत में आपको धन का प्रबंधन करके चलना होगा,अन्यथा आपका बजट गड़बड़ा सकता है। माह की शुरुआत में की गई फिजूलखर्ची बाद में आपके लिए कर्ज लेने का बड़ा कारण बन सकती है। इस दौरान सुख-सुविधा से जुड़ी चीजों पर जेब से अधिक धन खर्च हो सकता है।

सिंह

सिंह के लिए जुलाई का महीना काफी उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है। माह की शुरुआत में आपको शुभता व सफलता दोनों का साथ मिलेगा। आपके इष्टमित्र, रिश्तेदार आपके काम में सहयोग करते नजर आएंगे। प्रेम संबंध में भी हंसी-खुशी फल बीतेंगे लेकिन माह के दूसरे सप्ताह में आपको किसी के साथ हास-परिहास करते समय बेहद सावधानी बरतनी है, अन्यथा अपने भी आपसे नाराज होकर साथ छोड़ सकते हैं।

कन्या

कन्या राशि के जातकों को जुलाई महीने की शुरुआत में करिअर-कारोबार में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। इस दौरान न सिर्फ व्यवसाय में मनचाहा लाभ होगा बल्कि कारोबार में विस्तार का सपना भी साकार होगा। नौकरीपेशा लोगों को अपने सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग प्राप्त होगा। आय के नए स्रोत बनेंगे। परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है।

तुला

तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना अत्यंत ही शुभ और सफल होने जा रहा है। माह की शुरुआत में आपको घर और बार दोनों जगह लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। कार्यक्षेत्र में सीनियर आपके कामकाज की तारीफ करेंगे। उच्च पद की प्राप्ति या फिर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी मिल सकती है।

वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों लिए जुलाई माह का पूर्वार्ध कुछ एक परेशानियों और चिंताओं को लिए रहने वाला है। इस दौरान आपका अधिकांश समय घर-परिवार से लेकर कामकाज की परेशानियों को दूर करने में बीतेगा। जुलाई माह के पहले सप्ताह में भूमि-भवन आदि को लेकर परिवार के सदस्यों से तकरार हो सकती है। स्वजनों से मनचाहा सहयोग न मिल पाने पर मन थोड़ा खिन्न रहेगा।

धनु

धनु राशि के लिए यदि जुलाई महीने के पूर्वार्ध में अपने समय और ऊर्जा का प्रबंधन करने में कामयाब रहते हैं तो उन्हें प्रत्येक क्षेत्र में मनचाही सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ इन्हें अपनी वाणी और व्यवहार पर भी नियंत्रण रखना होगा। घर-परिवार और कार्यक्षेत्र में लोगों की छोटी-मोटी बातों को इग्नोर करना ही बेहतर रहेगा। माह की शुरुआत उन लोगों के लिए शुभ साबित हो सकती है। व्यवसाय के सिलसिले में की गई यात्रा शुभ साबित होगी।

मकर

मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना मिलाजुला रहने वाला है। इस महीने आपको अपनी सेहत और संबंध दोनों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत रहेगी। माह की शुरुआत में ही किसी प्रिय के साथ गलतफहमी या विवाद होने के कारण मन खिन्न रहेगा। इस दौरान आपको घर-परिवार और कार्यक्षेत्र में बहुत सोच-समझकर बात करने की जरूरत रहेगी। क्रोध करने और दूसरों को अपशब्द कहने से बचें।

कुंभ

कुंभ राशि के जातकों के लिए जुलाई माह का पूर्वार्ध का समय मनचाही सफलता और नए अवसर प्रदान करने वाला रहेगा। इस दौरान आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे,जिससे आपके भीतर आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। माह की शुरुआत में सुख-सुविधा से जुड़ी किसी चीज के क्रय से घर में खुशियों का माहौल रहेगा। इस दौरान आपको कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का खूब सहयोग मिलेगा।

मीन

मीन राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना अत्यंत ही शुभ साबित होने जा रहा है। माह की शुरुआत में संतान पक्ष की किसी बड़ी उपलब्धि से परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। इस दौरान घर में मांगलिक कार्यक्रम संपन्न हो सकते हैं। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा भी संभव है। यदि आप लंबे समय से भूमि-भवन या वाहन लेने चाह रहे थे तो इस माह आपकी यह कामना पूरी हो सकती है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को नई सरकार बनाने का न्योता दिया है. शुक्रवार सुबह नरेंद्र मोदी को एनडीए बैठक में संसदीय दल का नेता चुना गया, जिसके बाद वे शाम को राष्ट्रपति भवन द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे थे.मुलाकात के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘आज सुबह एनडीए की मीटिंग हुई थी. एनडीए के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दायित्व के लिए पसंद किया है. सभी एनडीए के साथियों ने राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी दी.‘उन्होंने कहा, ‘राष्ट्रपति जी ने अभी मुझे बुलाया था और मुझे नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की नियुक्ति दी है और मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की सूची के लिए सूचित किया है. मोटे तौर पर राष्ट्रपति जी को कहा है कि 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी.‘मोदी ने कहा, ‘बाकी जानकारी राष्ट्रपति भवन वर्क आउट करेगा. तब तक हम मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सुपुर्द करेंगे और उसके बाद शपथ समारोह होगा.‘

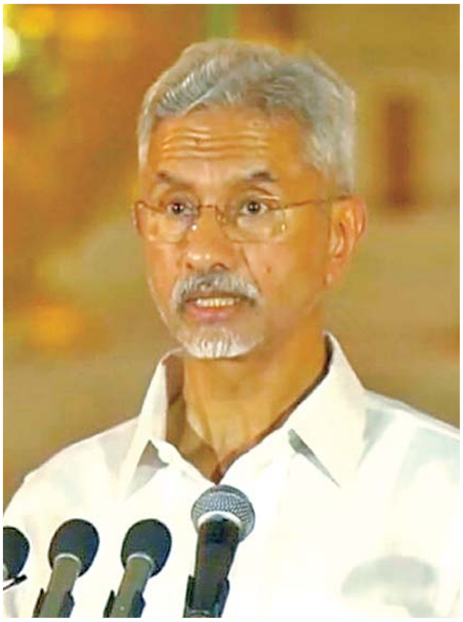

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ राष्ट्रपति भवन में केंद्रीय मंत्रिमंडल के शपथग्रहण समारोह में शिवहर सांसद लवली आनंद की मुलाकात व वार्तालाप की तस्वीर.

हे नरेन तू कभी घबराना मत...

कड़िया मुंडा ने नरेंद्र मोदी को भेजे गए पत्र में लिखा है कि आपके तीसरी पाली एनडीए के 60 के दशक (पंडित जवाहरलाल नेहरु) के बाद आपको पंत प्रधान बनने की कोटि-कोटि बधाई. आप एनडीए के नेता मनोनीत हुए हैं, इसकी भी बहुत-बहुत शुभकामना, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्षों श्रद्धेय अटल जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी से लेकर आज तक हमने विजय पराजय के साथ तत्कालीन जनसंघ से आज तक के भारतीय जनता पार्टी के 14 अध्यक्षों के साथ कार्य का अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं.

कड़िया मुंडा ने पत्र में लिखा है

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥

आपके अद्भुद, दैविक नेतृत्व ने आपने भारत को शीर्ष पर स्थापित किया है, और इस कारण आप यह विश्व की विशाल पार्टी संगठन के रूप में स्थापित हुआ है, आपके नेतृत्व में और सफलीभूत होगा और यह होना भी चाहिये, आज परिणाम प्रतिकूल आये हैं, इस परिस्थिति में भी आपकी स्थिखज्ञता को देख अचंभित हूं, आपके 4 जून और 5 जून के सम्बोधन को अक्षरशः सुन कर मैं गर्व से, अंतर से आपको साधु साधु-साधु ! कहने को विवश हूं.

आप यशस्वी हों यह मेरी शुभकामना है. साथ ही उम्र के इस पड़ाव पर झारखंड के संगठन की वास्तविक स्थिति और भगवान बिरसा के जन्मभूमि और अन्य 4 जनजातीय सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पराजय से आहत हूं. अध्यक्ष जी को आप इस मेरी चिंता से अवगत करायेंगे, साथ ही पूज्य अटल जी के झारखंड की चिंता भारतीय जनता पार्टी और आपका स्नेह इस राज्य को मिलता रहेगा यह विनयवत प्रार्थना है, मेरे 89 की उम्र में मेरी चिंता इस राज्य के जनजातीय स्मिता संस्कृति को ले कर है, इसे आप समझ सकते हैं. विपरीत परिस्थियों में आप विजयी यशस्वी हों यह कामना है.

कड़िया मुंडा ने नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में लक्ष्मण राज सिंह मरकाम की कविता समर्पित किया है -हे नरेन तू कभी घबराना मत, छली प्रपंची है बाहर भीतर इनके झांसे में आना मत है बाकी अभी तो कई धर्म युद्ध, सारा, भीतर के अंतर्मुखी निष्क्रिय क्रुद्ध विक्षुब्ध, हो अवसाद मुक्त संशय चक्रव्यूह निरुद्ध ये बहता अंतर का रक्त देख भरमाना मत, हे नरेन तू कभी घबराना मत .